

Weekly One Liners 10th to 16th August, 2026

पीएम मोदी का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण 2026: एआई प्रशिक्षण, ससंधारा, मुफ्त कोचिंग और विकसित भारत 2047

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2026 को लाल किले से भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित किया। लगभग 75 मिनट तक चले इस संबोधन में आत्मनिर्भरता, महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विनिर्माण, रक्षा, खेल, महिला प्रतिनिधित्व और युवा सशक्तिकरण जैसे कई विषयों को शामिल किया गया।

भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी चिह्नित किया गया, जब इस अवसर पर लाल किले में राष्ट्रीय गीत गाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 'विकसित भारत' की यात्रा के लिए 'युवा शक्ति' के महत्व पर बल दिया और ससंधारा, यानी सात धाराओं की अवधारणा प्रस्तुत की, जो भारत को आगे की वृद्धि की ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार होंगी।

पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक स्थल पर पहुंचने के बाद लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और उन्होंने सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के जवानों से मिलकर बने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया।

ध्वजारोहण समारोह को स्वदेशी 105 मिमी लाइट फील्ड गन का उपयोग करते हुए 1721 फील्ड बैटरी (सेरेमोनियल) द्वारा दी गई 21 तोपों की सलामी के साथ समन्वित किया गया।

ध्वजारोहण समारोह से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद किया।

वंदे मातरम के 150 वर्ष

वंदे मातरम के 150 वर्षों का स्मरण भारत के 2026 स्वतंत्रता दिवस समारोह की एक प्रमुख विशेषता थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया और उल्लेख किया कि देशभर में लहराते तिरंगे के साथ-साथ वंदे मातरम का नारा भारतीयों के दिलों में गूंज रहा था।

प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों के प्रति भी अपना समर्थन व्यक्त किया।

2047 तक विकसित भारत: पीएम मोदी का मुख्य उद्देश्य

पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश में बदलने के लक्ष्य को फिर से दोहराया, क्योंकि उस समय देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा।

उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को देश के 140 करोड़ से अधिक नागरिक मिलकर ही पूरा कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के विकास में पहले ही कुछ उल्लेखनीय बदलाव आ चुके हैं और अब देश के लक्ष्यों को और ऊंचा उठाया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे बताया कि गरीब, मध्यम वर्ग, युवा आदि सहित सभी वर्गों के नागरिकों के संकल्प ने भारत को अपना विकास हासिल करने में मदद की है।

पीएम मोदी के अनुसार, 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, जिसे उन्होंने भारत की विकास प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बताया।

आत्मनिर्भरता और "वोकल फॉर लोकल"

आत्मनिर्भरता उनके भाषण के मुख्य विषयों में से एक थी।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत को आवश्यक उत्पादों और तकनीकों के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और "वोकल फॉर लोकल" को मजबूत करने का आग्रह किया।

उन्होंने आगे कहा कि इस लक्ष्य को "मेक इन इंडिया" पहल के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, क्योंकि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा सुरक्षा

पीएम मोदी के अनुसार, महत्वपूर्ण खनिज और ऊर्जा सुरक्षा भारत के भविष्य के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

चूंकि सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डेटा सेंटर जैसे नए युग के उद्योगों को ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की सुनिश्चित आपूर्ति की आवश्यकता होती है, पीएम मोदी ने कहा कि भारत को इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत है।

पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण खनिज गलियारे से संबंधित भारत की पहलों के बारे में बात की और कहा कि कई देशों ने इस संबंध में भारत पर अपना भरोसा जताया है।

उनके अनुसार, डेटा सेंटरों, सेमीकंडक्टर प्लांटों और अन्य प्रौद्योगिकी-गहन उद्योगों की बढ़ती मांग के कारण एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति

भारत के आत्मनिर्भरता अभियान में सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर जोर दिया गया।

पीएम मोदी के अनुसार, भारत ने तीन सेमीकंडक्टर सुविधाएं स्थापित की हैं, और वहां पहले से ही उत्पादन जारी है, और भविष्य में ऐसी और सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

एक घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग बनाने से भारत को आवश्यक सेमीकंडक्टरों के लिए विदेशों से आयात पर निर्भरता कम करने और वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।

₹85,000 करोड़ का गहरे समुद्र में अन्वेषण

गहरे समुद्र में अन्वेषण भी भारत की उन पहलों में से एक था जिसके बारे में पीएम मोदी ने अपने भाषण में बात की।

पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में शुरू की गई समुद्र मंथन पहल के माध्यम से गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए ₹85,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

पीएम मोदी ने नए तेल भंडार के लिए भारत के अपतटीय क्षेत्र के अन्वेषण का भी उल्लेख किया, जहां उन्होंने कहा कि तटरेखा के जिन विशाल क्षेत्रों को भारत अन्वेषण के लिए "नो गो" क्षेत्र मानता था, अब उनका अन्वेषण किया जाएगा।

ऐसे अन्वेषणों के पीछे का लक्ष्य घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना और नए रणनीतिक संसाधनों को खोजना है।



ALL EXAMS, **ONE** SUBSCRIPTION

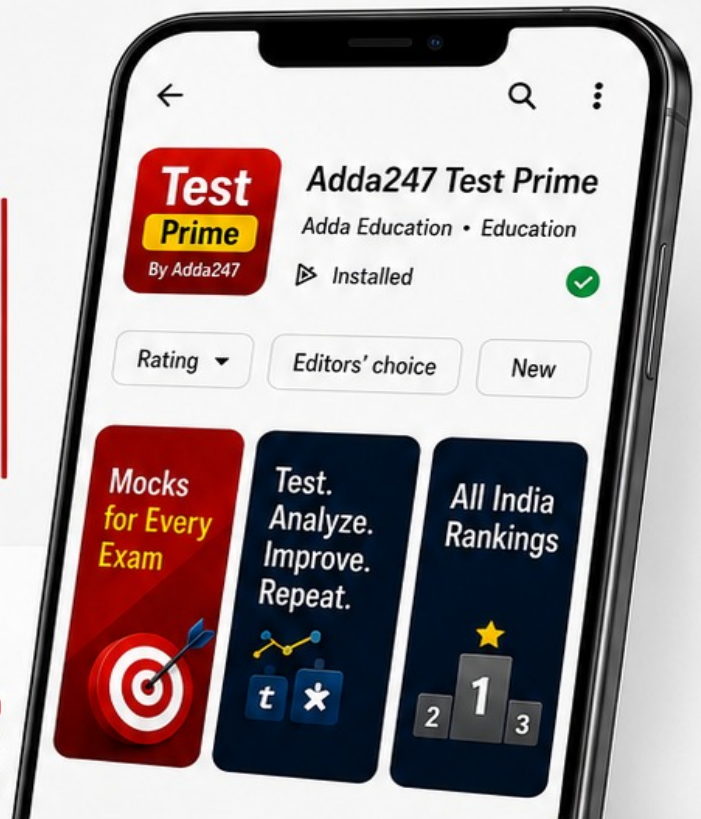


Test. Analyze. Improve. Repeat.



*Don't just
prepare.
Perform.*

Test Prime – built only
for mock tests.



1,50,000+
Mock Tests



25,000+
Previous Year
Papers



800+
Exam
Covered



500%
Refund on
Selection



5 lakh+
Free Quizzes



Daily
Free PDFs



Top Alerts
Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- ✓ Multilingual
- ✓ Detailed Solution
- ✓ Strong and Weak Areas
- ✓ All India Rankings



Safe & Reliable



Trusted by
Lakhs of Aspirants

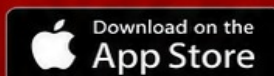


Your Success,
Our Mission



**DOWNLOAD
TEST PRIME**

Your Success Partner!



2047 तक भारत का परमाणु ऊर्जा लक्ष्य

भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन योजनाएं पीएम मोदी के भाषण का हिस्सा थीं।

पीएम मोदी ने बताया कि 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के भारत के लक्ष्य और नए परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के विकास के बारे में जानकारी दी।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन का यह विस्तार बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने की भारत की दीर्घकालिक योजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।

भारत की पाइप गैस, सौर ऊर्जा और घरेलू ऊर्जा उत्पादन

पीएम मोदी ने पाइप गैस अवसंरचना के विकास के बारे में बात की, यह उल्लेख करते हुए कि 2014 से पहले केवल लगभग 70 शहरों में पाइप गैस की सुविधा थी, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 700 से अधिक शहरों में हो गई है।

इससे 1.45 करोड़ से अधिक परिवारों को उनकी पाइप गैस सुविधा में मदद मिली है।

सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में बात करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि 50 लाख से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा प्राप्त हुई है।

रेलवे का विद्युतीकरण और हाइड्रोजन ट्रेन

प्रधानमंत्री ने भारत की रेलवे प्रणाली के विकास का उल्लेख किया। अपने भाषण में, उन्होंने उल्लेख किया कि रेलवे विद्युतीकरण की शुरुआत 1925 में हुई थी, लेकिन पिछले 90 वर्षों में प्रणाली का केवल 30 प्रतिशत ही विद्युतीकृत हो पाया। उन्होंने कहा कि शेष विद्युतीकरण प्रक्रिया भारत में पिछले दस वर्षों में हुई है।

पीएम मोदी के अनुसार, रेलवे विद्युतीकरण प्रक्रिया से ईंधन के आयात में कमी आई है और पर्यावरणीय लाभ भी मिले हैं।

पीएम मोदी के अनुसार, भारत ने हाइड्रोजन ट्रेनों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन को इस बात के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया कि कैसे भारत रेल प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर प्रगति कर रहा है।

एफटीए और एमएसएमई के अवसर

पीएम मोदी ने कहा कि भारत 40 देशों के साथ एफटीए कर रहा है। उन्होंने भारतीय एमएसएमई को इन समझौतों का उपयोग करने और अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय उत्पादों को गुणवत्ता, लागत और प्रतिस्पर्धात्मकता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखते हुए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाना चाहिए।

विशेष रूप से, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की समुद्री खाद्य निर्यात क्षमता को उजागर किया। उन्होंने केरल, गुजरात, तमिलनाडु और बंगाल के अवसरों की ओर इशारा किया।

सप्तधारा: विकसित भारत के लिए सात धाराएं

भाषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक शायद पीएम मोदी द्वारा सप्तधारा की घोषणा थी, जिसका अर्थ है विकास की सात धाराएं।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत अगले स्तर के सुधार चरण में प्रवेश कर रहा है और भारत को "रिफॉर्म एक्सप्रेस" के रूप में वर्णित किया।

सात धाराएं हैं,

विनिर्माण

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण
प्रौद्योगिकी और नवाचार
गति शक्ति
रक्षा शक्ति
ग्रीन और ब्लू अर्थव्यवस्था
सॉफ्ट पावर

भारत की अंतरराष्ट्रीय कॉरपोरेट आकांक्षाएं

प्रधानमंत्री ने भारतीय कॉरपोरेट्स से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा लक्ष्य रखने के लिए कहा।

उन्होंने सवाल किया कि आने वाले दशक में भारत के फॉर्च्यून 500 में 50 कॉरपोरेशन क्यों नहीं होने चाहिए।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कम से कम एक भारतीय बैंक को दुनिया के शीर्ष पांच बैंकों में शामिल होने की जरूरत है।

इसी तरह, कम से कम एक भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनी को दुनिया की शीर्ष पांच फार्मास्युटिकल कंपनियों की सूची में होने की जरूरत है।

एक करोड़ युवाओं को एआई में प्रशिक्षित किया जाएगा

युवाओं को सशक्त बनाना भाषण के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक था। पीएम मोदी ने बताया कि एक करोड़ युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

यह भारत के युवाओं को एआई और अन्य उन्नत तकनीकों के प्रभुत्व वाले युग के लिए तैयार करने के प्रयासों का हिस्सा है।

इसके अलावा, उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेले इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को मिले फायदों का उल्लेख किया।

प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग

इसके अलावा, पीएम मोदी ने युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर्स का नेटवर्क बनाने की घोषणा की।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसे की कमी छात्रों की परीक्षा की तैयारी में बाधा न बने।

विशेष रूप से, यह घोषणा उन लोगों के लिए मददगार है जो सरकारी नौकरियों और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।

₹1 लाख करोड़ से अधिक का नवाचार कोष

प्रधानमंत्री ने ₹1 लाख करोड़ से अधिक के नवाचार कोष के बारे में बात की है।

यह भारत और इसके प्रौद्योगिकी क्षेत्र के युवा नवोन्मेषकों को नवाचार को बढ़ावा देने और अवसर प्रदान करने के बारे में है।

यह उन योजनाओं में से एक है जो भारत को एक ऐसे नवोन्मेषी राष्ट्र में बदलने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों और व्यवसायों का उत्पादन करता है।

2036 ओलंपिक और 2030 राष्ट्रमंडल खेल

पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में खेलों पर काफी जोर दिया गया। प्रधानमंत्री के अनुसार, भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा और उसकी नजर 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने पर भी है।

उनके अनुसार, भारत काफी संख्या में ओलंपिक खेलों में भाग नहीं लेता है। इस अंतर को ठीक करने के लिए, उन्होंने 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक टैलेंट हंट अभियान के बारे में बात की है।

यहां उद्देश्य बच्चों में खेल प्रतिभा की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे उन क्षेत्रों में सक्षम हों जहां भारत पीछे रहा है।

"जो खेले, वो खिले" – संक्षेप में उनका संदेश।

नक्सलवाद और 'दिमागी नक्सल'

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य भारत को नक्सल-मुक्त बनाना है।

उनके अनुसार, उन क्षेत्रों में बड़े बदलाव आए हैं जो पहले सशस्त्र नक्सलियों की समस्या का सामना करते थे।

इसके अलावा, उनके अनुसार, नक्सलियों ने पैसे और नागरिकों की जान दोनों के मामले में भारी नुकसान पहुंचाया है।

हालांकि, यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रधानमंत्री ने 'दिमागी नक्सलों' का भी उल्लेख किया।

नागरिक सुरक्षा नेटवर्क

इसके अलावा, उन्होंने घोषणा की कि एक नागरिक सुरक्षा नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

इस परियोजना का उद्देश्य किसी भी आपातकाल या ऐसी स्थिति में तैयारी और लचीलेपन को बढ़ाना है जिसमें नागरिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।

महिला आरक्षण और नारी शक्ति

इसके अलावा, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भाषण में चर्चा किया गया एक और महत्वपूर्ण विषय था।

पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख किया जो कानून में निर्धारित शर्तों के अधीन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, उन्होंने सभी विचारधाराओं की राजनीतिक पार्टियों से इस पहल का समर्थन करने का अनुरोध किया और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की मांग की।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की क्षमता को स्वीकार किया जाना चाहिए और भारतीय राजनीति में उनका अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

पीएम मोदी ने युवाओं से जनगणना के लिए अपील की

भाषण के अंत में, पीएम मोदी ने युवाओं से जनगणना की प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की।

संकट प्रबंधन और "नागरिक देवो भव" की भावना

प्रधानमंत्री ने महामारी के बाद की स्थिति के कारण भारत के सामने आई चुनौतियों का उल्लेख किया, अर्थात् संघर्ष और वैश्विक ऊर्जा संकट।

विशेष रूप से, वैक्सीन, ईंधन, डीजल और उर्वरकों की कमी को लेकर आशंकाएं और अफवाहें थीं।

प्रधानमंत्री के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए गए कि नागरिकों के साथ-साथ किसानों को भी इन संकटों की पूरी मार न झेलनी पड़े।

"प्रधानमंत्री ने 'नागरिक देवो भव' की भावना का उल्लेख किया, जिसमें नागरिक को शासन का केंद्र बिंदु बताया गया।"

इसके अलावा, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उच्च कीमतों के बावजूद किसानों को नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध कराए गए उर्वरकों का उदाहरण दिया।

भारत में गरीबी में कमी

देश में गरीबी में कमी एक और उपलब्धि थी।

विशेष रूप से, पीएम मोदी ने कहा कि निर्दिष्ट अवधि में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बचाया गया, और उन्होंने भारत के विकास में विभिन्न सामाजिक और आर्थिक स्तरों के नागरिकों के योगदान का उल्लेख किया।

विशेष रूप से, उन्होंने कहा कि नागरिकों की सामूहिक इच्छाशक्ति के कारण देश के विकास को रोकना अब लगातार कठिन होता जा रहा है।

शासन का परिवर्तन और अवसंरचना विकास

प्रधानमंत्री ने पिछले दशक के दौरान शासन प्रणाली में हुए परिवर्तनों का भी उल्लेख किया।

पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, शासन का तरीका बदल गया है, साथ ही अवसंरचना का नवीनीकरण भी हुआ है।

विशेष रूप से, पीएम मोदी ने भारत के शहरों में मेट्रो रेल के विकास और अवसंरचना विकास में तेजी का उल्लेख किया।

आत्मनिर्भर भारत और संसाधनों का घरेलू अन्वेषण

आत्मनिर्भरता प्रधानमंत्री के भाषण का मुख्य विषय बन गई।

विशेष रूप से, उन्होंने कहा कि देश को ऊर्जा के विदेशी स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्वयं के संसाधनों का अन्वेषण करना चाहिए और घरेलू क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने विशेष रूप से तेल और अन्य संसाधनों के अपतटीय अन्वेषण के महत्व पर जोर दिया, जो भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है।

इस संदर्भ में ₹85,000 करोड़ के समुद्र मंथन आवंटन का उल्लेख किया गया।

75 मिनट का स्वतंत्रता दिवस संबोधन

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया स्वतंत्रता दिवस संबोधन लगभग 75 मिनट तक चला।

यह भारत की स्वतंत्रता के समय से लेकर अब तक की प्रगति के बारे में विचारों के साथ-साथ एआई, विनिर्माण, ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, रक्षा, अवसंरचना, खेल, महिलाओं, युवाओं और सुधारों जैसे क्षेत्रों पर कई भविष्य-केंद्रित घोषणाओं का मिश्रण था।

पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण 2026 की मुख्य बिन्दु

भारत ने अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया।

इस समारोह ने वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी चिह्नित किया।

पीएम मोदी ने 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को दोहराया।

विकास योजना के लिए सप्तधारा दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया।

एक करोड़ युवाओं को एआई में प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक मुफ्त कोचिंग नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

₹1 लाख करोड़ से अधिक के नवाचार कोष की घोषणा की गई।

भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता की योजना बना रहा है।

भारत महत्वपूर्ण खनिजों पर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहा है।

पीएम मोदी के अनुसार, तीन सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र अब चालू हैं।

गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए ₹85,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

भारत 40 से अधिक देशों के साथ एफटीए पर काम कर रहा है।

पीएम मोदी के अनुसार, रेलवे विद्युतीकरण 100% तक पहुंच गया है।

50 लाख से अधिक परिवार सौर ऊर्जा से संचालित हैं।

भारत अगले दशक में 50 फॉर्च्यून 500 कंपनियां रखने की योजना बना रहा है।

कम से कम एक भारतीय बैंक को वैश्विक सूची में शीर्ष पांच में आना चाहिए। कम से कम एक भारतीय फार्मा कंपनी को दुनिया में शीर्ष पांच में स्थान मिलना चाहिए।

भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का भी लक्ष्य रखेगा।

5-15 आयु वर्ग के लिए खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम की शुरुआत।

पीएम मोदी ने भारत के नक्सल-मुक्त बनने के लक्ष्य को दोहराया।

एक नागरिक सुरक्षा नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।

पीएम मोदी ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लक्ष्य के समर्थन की अपील की।

युवाओं से जनगणना के दौरान सटीक डेटा प्रदान करने में अपने परिवारों की मदद करने का आग्रह किया गया।

पीएम मोदी द्वारा आत्मनिर्भर, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया गया।

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25: राष्ट्रपति 115 कलाकारों को सम्मानित करेंगी

2026 में भारत की प्रदर्शन कलाओं के लिए, भारत की माननीय राष्ट्रपति 13 अगस्त, 2026 को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान करने वाली हैं। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए कुल 115 कलाकारों का चयन किया गया है, जिसमें संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाएं, कठपुतली, वाद्य निर्माण और अन्य प्रदर्शन कलाओं जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

ये पुरस्कार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे भारत के सांस्कृतिक संस्थानों, प्रदर्शन कलाओं और राष्ट्रीय सम्मानों को प्रदर्शित करते हैं।

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024-25

विशेष पुरस्कार समारोह 13 अगस्त, 2026 को सुबह 11:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है, जहां भारत की राष्ट्रपति चयनित कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करेंगी।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉ संध्या पुरेचा समारोह में शामिल होने वाली कुछ प्रमुख हस्तियां हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 115 पुरस्कार विजेताओं और फेलो का चयन भारत की विविध प्रदर्शन कलाओं में से किया गया है।

संगीत नाटक अकादमी क्या है?

संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक की भारत की राष्ट्रीय संस्था है। यह पुरस्कार प्रदर्शन कला के क्षेत्र में किए गए असाधारण और विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं।

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों में शास्त्रीय संगीत और नृत्य के साथ-साथ रंगमंच, लोक और जनजातीय परंपराएं और अन्य संबंधित प्रदर्शन कलाएं शामिल हैं। संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार अकादमी फेलोशिप या अकादमी रत्न कहलाता है। एक फेलो को ₹3 लाख दिए जाते हैं, जबकि एक अकादमी पुरस्कार में ₹1 लाख की पुरस्कार राशि और एक ताम्रपत्र व अंगवस्त्र शामिल होता है।

संगीत नाटक अकादमी फेलो (अध्येता) — अकादमी रत्न

क्रमांक	फेलो
1	रामलाल बारेथ
2	ए. वी. आनंद
3	रीता गांगुली
4	पुरु दधीच
5	चित्तरंजन ज्योतिषी
6	पसुमार्थी रत्नैया शर्मा
7	सुधारानी रघुपाथी

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024

संगीत

क्रमांक	कलाकार	क्षेत्र / अनुशासन
1	अरुण नागेश काशलकर	हिंदुस्तानी गायन
2	निर्मल्या दे	हिंदुस्तानी गायन - ध्रुपद
3	भारत भूषण गोस्वामी	हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र - सारंगी
4	संजय मुखर्जी	हिंदुस्तानी वाद्य संगीत - तबला
5	कृष्ण वागीश	कर्नाटक गायन
6	एन. विजय शिव	कर्नाटक गायन
7	ए. एस. कृष्णन कर्नाटक	वाद्य संगीत - शोकगीत
8	कोमांदुरी शेफाद्री कर्नाटक	वाद्ययंत्र - वायलिन
9	राकेश चौरसिया	रचनात्मक और प्रयोगात्मक - बांसुरी
10	प्रभाती मुखर्जी	संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ - सुगम संगीत
11	आनंद भाटे	संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ - अभंग
12	समंदर खान मंगानियार	संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ - मांड

नृत्य

क्रमांक	कलाकार	क्षेत्र / अनुशासन
1	राजेश्वरी साईनाथ	भरतनाट्यम
2	बिपुल चंद्र दास	कथक
3	राजकुमारी थंबलसना देवी	मणिपुरी
4	वीना मूर्ति विजय	कुचिपुडी
5	विचित्रानंद स्वैन	ओडिसी
6	प्रेमा ओझाह बोरबायन	सत्रिया नृत्य
7	श्रीदेवी राजन	मोहिनीअट्टम
8	नृपेन साहिस	छाऊ
9	शशिधरन नायर	रचनात्मक और प्रयोगात्मक
10	कलामंडलम उन्नीकृष्णन	नृत्य के लिए संगीत - कथकली
11	कुमार सूर्य नारायण	नृत्य के लिए संगीत

थिएटर

क्रमांक	कलाकार	क्षेत्र / अनुशासन
1	सतीश दवे	निर्देशन
2	टी. एस. नागभरना	निर्देशन
3	रवि चतुर्वेदी	निर्देशन
4	ओम कटारे	निर्देशन
5	गुम्माडी गोपाल कृष्ण राव	अभिनय
6	वागई चंदरसेकर	अभिनय
7	अरुण नलवडे	अभिनय
8	धीरेन डी. मर्चेट	एलाइड थिएटर आर्ट्स - लाइटिंग
9	दिनेश कुमार पोद्दार	एलाइड थिएटर आर्ट्स - लाइटिंग
10	मुकुंद राम मराठे	पारंपरिक रंगमंच - संगीत नाटक

लोक कला, आदिवासी कला, कठपुतली कला, मुखौटा कला और वाद्य यंत्र निर्माण

क्रमांक	कलाकार	क्षेत्र / अनुशासन
1	दुर्शेती रामैया	लोक संगीत, तेलंगाना
2	के. मुरुगन	लोक नृत्य, पुडुचेरी
3	एस. सी. शर्मा	लोक एवं आदिवासी संगीत, कर्नाटक
4	आतमजीत सिंह	नौटंकी, उत्तर प्रदेश
5	महेन्द्र राम	लोक संगीत, बिहार
6	बुटन देवी और सोमारी देवी (संयुक्त)	लोक नृत्य, झारखंड
7	रणजीत कुमार नाग	लोक नृत्य - संबलपुरी, ओडिशा
8	हवा सिंह	लोक संगीत, हरियाणा
9	वेस्वुजो फ़ेसाओ	लोक संगीत और नृत्य, नागालैंड
10	गुलाबी सपेरा	लोक नृत्य, राजस्थान - कालबेलिया
11	लौरेम्बाम बेदाबती	लोक संगीत, मणिपुर
12	सुभाष नारायण नकाशे	लोक नृत्य, महाराष्ट्र
13	किशोरभाई सोमभाई मिस्त्री	वाद्य यंत्र निर्माण - रुद्र वीणा

समग्र और अन्य

क्रमांक	कलाकार	क्षेत्र / अनुशासन
1	टीएस सत्यवती	संगीत में समग्र योगदान
2	बोलेटी रंगामणि	नृत्य में समग्र योगदान
3	शुभदा मनोहर वरदकर	नृत्य प्रदर्शन कला में छात्रवृत्ति
4	तासी चौधरी	कला समीक्षा - प्रदर्शन कला
5	सुनंदा नायर	विदेश में - नृत्य (मोहिनीअट्टम)

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2025

संगीत

क्रमांक	कलाकार	क्षेत्र / अनुशासन
1	कृष्णा मोहन पाठक	हिंदुस्तानी वोकल - ध्रुपद
2	सुरेश गंधर्व	हिंदुस्तानी वोकल
3	शैलेश भगवत	हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र - शहनाई
4	ज्योति गणपति हेगड़े	हिंदुस्तानी वाद्ययंत्र - रुद्र वीणा
5	पंतुल रामा	कर्नाटक वोकल
6	पापनासम अशोक रमानी	कर्नाटक वोकल
7	त्रिपूनिथुरा एन राधाकृष्णन	कर्नाटक वाद्ययंत्र - घटम
8	अनूर आर. अनंत कृष्ण शर्मा	कर्नाटक वाद्ययंत्र - मृदंगम
9	डी. श्रीनिवास कर्नाटक	वाद्ययंत्र - वीणा
10	युगंतर सिंदूर	संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ - सुगम संगीत
11	सच्चीदानंद दास अन्य	संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ - मर्दाला
12	सीमा अनिल सहगल	संगीत की अन्य प्रमुख परंपराएँ - सुगम संगीत

नृत्य

क्रमांक	कलाकार	क्षेत्र / अनुशासन
1	रोजा कन्नन	भरतनाट्यम
2	कृष्णा मोहन मिश्र महाराज, वासवती मिश्रा और राम मोहन महाराज (तीनों)	कथक
3	कलामंडलम कृष्णकुमार	कथकली
4	इरेंगबम नलिनी देवी	मणिपुरी
5	सीता नागाजोथी और पी. नागाजोथी (संयुक्त)	मणिपुरी
6	मल्लिका कंडाली	सत्रिया नृत्य
7	गिरिजा चंद्रन	मोहिनीअट्टम
8	पागुलु जेना	छऊ - मयूरभंज
9	कनियाल हरिप्रसाद	नृत्य के लिए संगीत - भरतनाट्यम
10	भास्कर ज्योति ओझा	नृत्य के लिए संगीत - सत्तरिया
11	एस. कुमार	नृत्य और नृत्य रंगमंच की प्रमुख परंपराएँ - भगवतमेल

थिएटर

क्रमांक	कलाकार	क्षेत्र / अनुशासन
1	कपिलदेव चंद्रकांत शुक्ला	निर्देशन
2	कल्लोल भट्टाचार्य	निर्देशन
3	नवदीप कौर	निर्देशन
4	प्रमोद ज्ञानदेव पवार	निर्देशन
5	सुबोध पटनायक	निर्देशन
6	चेतना दास	अभिनय
7	सुरेश कुमार हज्जू	अभिनय
8	मन्मथ लाल सराफ	अभिनय
9	अशोक पटकी	एलाइड थिएटर आर्ट्स - थिएटर के लिए संगीत
10	उषा नांगियार	नाट्यकला की अन्य प्रमुख परंपराएँ - नांगियारकूथ

लोक कला, आदिवासी कला, कठपुतली कला, मुखौटा कला और वाद्य यंत्र निर्माण

क्रमांक	कलाकार	क्षेत्र / अनुशासन
1	अनुप रंजन पांडे	लोक संगीत, छत्तीसगढ़
2	भेरू सिंह चौहान	लोक संगीत, मध्य प्रदेश - निर्गुणी
3	सूर्य कुमार देवबर्मा	लोक नृत्य, त्रिपुरा
4	जोगिंदर सिंह हब्बी	लोक नृत्य, हिमाचल प्रदेश
5	रोमालो राम	लोक संगीत एवं नृत्य, जम्मू और कश्मीर
6	हरमनप्रीत सिंह	लोक नृत्य, पंजाब
7	अली मोहम्मद	लोक संगीत, लद्दाख
8	डोमिन कार्बाक	लोक नृत्य, अरुणाचल प्रदेश
9	के. रोसियामा	लोक नृत्य, मिजोरम
10	रानी मारिंग	वाद्य यंत्र निर्माण
11	सुशांत कुमार	मुखौटा बनाना - छऊ
12	मंगला प्रसाद शर्मा	वाद्य यंत्र निर्माण

समग्र और अन्य

क्रमांक	कलाकार	क्षेत्र / अनुशासन
1	कुणाल	थिएटर में समग्र योगदान
2	मनीषा साठे	नृत्य में समग्र योगदान - कथक
3	राकेश सिन्हा	समग्र योगदान - कला फोटोग्राफी
4	मंजरी सिन्हा	कला समीक्षा - प्रदर्शन कला
5	टी.एस. नंदकुमार	विदेश में - संगीत (मृदंगम)

पुलिस और अग्निशमन सेवा कर्मियों को 301 वीरता पदक प्रदान किए गए।

स्वतंत्रता दिवस 2026 के उपलक्ष्य में असाधारण वीरता और कर्तव्यनिष्ठा के लिए पुलिस बल और अग्निशमन सेवाओं के 301 सदस्यों को वीरता पदक प्रदान किए गए हैं। इनमें से अधिकांश पुरस्कार उन लोगों को मिले हैं जो उग्रवादी आंदोलन (LWE) से प्रभावित क्षेत्रों में सेवारत हैं। कुल मिलाकर, पुलिस बल, अग्निशमन विभाग, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के 1,057 सदस्यों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

301 वीरता पदक प्रदान किए गए

कुल 301 वीरता पदकों में से 272 पदक पुलिस कर्मियों को और 29 पदक अग्निशमन सेवा कर्मियों को प्रदान किए गए हैं।

सरकार के अनुसार, उपर्युक्त पदक उन असाधारण वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दिए गए हैं जिनमें जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध की रोकथाम या अपराधियों की गिरफ्तारी शामिल थी। इसमें शामिल जोखिम का आकलन उनके आधिकारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संदर्भ में किया जाता है।

वीरता पदकों का क्षेत्र अनुसार वितरण

विभिन्न क्षेत्रों के कर्मियों को कुल 301 वीरता पदक प्रदान किए गए हैं।

- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी
- जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के 51 कर्मी
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 12 कर्मी
- अन्य क्षेत्रों से 41 कर्मी

LWE से प्रभावित क्षेत्रों के कर्मियों को दिए गए पदकों की अधिकतम संख्या चरमपंथियों की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा बलों के काम करने की चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाती है।

1,057 कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया

वीरता पदकों के अलावा, पुलिस, अग्निशमन सेवा, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के 1,057 कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अन्य कई पुरस्कार भी दिए गए हैं।

ये पुरस्कार वीरता और सेवा के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित हैं, जहां पुरस्कार साहसी कार्यों और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण दोनों के लिए दिए जाते हैं।

92 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाले

इसके अलावा, केंद्र की ओर से 92 पुलिस और संबद्ध सेवा कर्मियों के लिए विशिष्ट सेवा पदक (PSM) की घोषणा भी की गई।

वितरण इस प्रकार था,

- 83 पुलिस सेवा कर्मी
- 4 अग्निशमन सेवा कर्मी
- 3 नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड कर्मी
- 2 सुधार सेवा कर्मी

राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक किसी अधिकारी की विशेष और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

उत्कृष्ट सेवा के लिए 664 पदक प्रदान किए गए

इसके अतिरिक्त, 664 मेधावी सेवा पदक (MSM) भी प्रदान किए गए। यह पदक सूझबूझ और कर्तव्यनिष्ठा से युक्त सहायनीय सेवा को सम्मानित करता है।

इन व्यक्तियों में शामिल हैं,

- पुलिस बल के 606 व्यक्ति
- दमकल सेवा से जुड़े 28 व्यक्ति
- नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के 18 व्यक्ति
- सुधार सेवाओं से जुड़े 12 व्यक्ति

वीरता पदक और राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक के साथ-साथ, ये सम्मान भारत की आंतरिक सुरक्षा सेवाओं, आपातकालीन सेवाओं और सुधार सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के योगदान पर जोर देते हैं।

राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक (PSM) 2026 — राज्य/संगठन-वार विजेता

आंध्र प्रदेश

- श्री विजय कुमार गुडी - महानिरीक्षक
- श्री वेंकट रामी रेड्डी बालनकारी - महानिरीक्षक

असम

- श्री देवोज्योति मुखर्जी — महानिरीक्षक

बिहार

- श्री संजय कुमार — महानिरीक्षक
- श्रीमती बीना कुमारी - पुलिस अधीक्षक

छत्तीसगढ़

- श्री मोती लाल कोटवानी — उप महानिरीक्षक

दिल्ली NCT

- श्री दिनेश कुमार गुप्ता — उप महानिरीक्षक
- श्री राजेश कुमार — सहायक उप निरीक्षक

गुजरात

- श्री अमित कुमार किशोर विश्वकर्मा - अपर महानिदेशक
- श्री बहादुरसिंह अभेसिंह चुडासमा - पुलिस उपाधीक्षक

हरियाणा

- श्रीमती सुशीला कौशिक - उप-निरीक्षक

हिमाचल प्रदेश

- श्री गुरदेव चंद शर्मा - उप महानिरीक्षक

झारखंड

- श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा - महानिरीक्षक

कर्नाटक

- श्री धर्मेन्द्र हुब्बा नंजप्पा कल्लेगौडाना कोप्पलु - सहायक पुलिस आयुक्त

केरल

- श्री शशिधरन शंकरन एजुथाचन किज़हक्केकरा - पुलिस अधीक्षक

मध्य प्रदेश

- श्री धर्मवीर सिंह - पुलिस अधीक्षक
- श्री सुनील कुमार पांडे — उप महानिरीक्षक
- श्री अनिल कुमार भदौरिया-निरीक्षक
- श्री राज लोचन प्रसाद दुबे - हवलदार

महाराष्ट्र

- श्री शिरीष रवीन्द्र जैन - अतिरिक्त महानिदेशक
- श्री सुभाष नानासाहेब भुजंग - पुलिस उपाधीक्षक
- श्री संजय राजाराम वायचले - सहायक उप निरीक्षक

मणिपुर

- श्री लोकहेन्द्रो सिंह अरंबम - सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक

मिजोरम

- श्रीमती मीनू चौधरी - अतिरिक्त महानिदेशक

नागालैंड

- श्री विडेलाली ज़शुमो - महानिरीक्षक

ओडिशा

- श्री संजीव पांडा — अतिरिक्त महानिदेशक
- श्रीमती स्मितरानी मोहंती - पुलिस उप अधीक्षक

पंजाब

- श्री बलजीत सिंह - निरीक्षक

राजस्थान

- श्री सुरेंद्र सिंह राणावत - सहायक पुलिस आयुक्त
- श्री महेंद्र कुमार भगत - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

तमिलनाडु

- श्री जे. विजय आनंद - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
- श्री के. रामचंद्रन - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
- श्री एस कुमार — सहायक कमांडेंट

तेलंगाना

- श्री नरसैया जोगुला - अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
- श्री आर.जगदीश्वर रेड्डी - पुलिस अधीक्षक

उत्तर प्रदेश

- श्री ध्रुवकांत ठाकुर - पुलिस महानिदेशक
- श्रीमती पद्मजा चौहान - अतिरिक्त महानिदेशक
- श्री प्रशांत कुमार — अतिरिक्त महानिदेशक
- श्री देव नारायण यादव — सहायक कमांडेंट
- श्री अजय कुमार त्रिपाठी — सहायक कमांडेंट
- श्री विकास श्रीवास्तव - पुलिस उपाधीक्षक

पश्चिम बंगाल

- श्री अजय नंद - पुलिस आयुक्त

पुदुचेरी

- श्री रंगनाथन बी - पुलिस अधीक्षक

जम्मू और कश्मीर

- श्री शौकत हुसैन शाह - वरिष्ठ अधीक्षक

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य संगठन

असम राइफल

- श्री प्रीतम लाल - सूबेदार मेजर

सीमा सुरक्षा बल (BSF)

- श्री मांगी लाल गर्ग - महानिरीक्षक
- श्री चारु ध्वज अग्रवाल - महानिरीक्षक
- श्री अशोक कुमार — उप महानिरीक्षक
- श्री धीरेंद्र सिंह सिंधु - उप महानिरीक्षक
- श्री अमरवीर यादव — सेकंड-इन-कमांड



ALL EXAMS, **ONE** SUBSCRIPTION

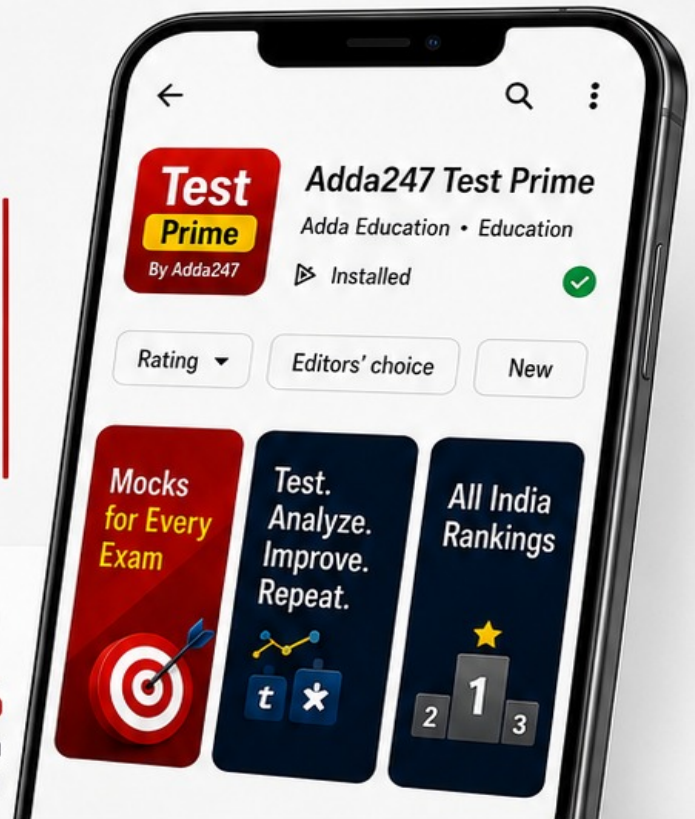


Test. Analyze. Improve. Repeat.



*Don't just
prepare.
Perform.*

Test Prime – built only
for mock tests.



1,50,000+
Mock Tests



25,000+
Previous Year
Papers



800+
Exam
Covered



500%
Refund on
Selection



5 lakh+
Free Quizzes



Daily
Free PDFs



Top Alerts
Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- ✓ Multilingual
- ✓ Detailed Solution
- ✓ Strong and Weak Areas
- ✓ All India Rankings



Safe & Reliable



Trusted by
Lakhs of Aspirants

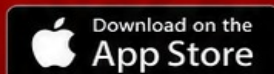
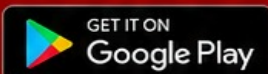


Your Success,
Our Mission



**DOWNLOAD
TEST PRIME**

Your Success Partner!



केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)

- श्रीमती हरप्रीत कौर सोही - महानिरीक्षक
- श्री मोहन एस - सहायक कमांडेंट

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)

- श्री नरेंद्र कुमार सिंह — महानिरीक्षक
- श्री एम. धिनकरन - उप महानिरीक्षक
- श्री मनीष शर्मा — कमांडेंट
- श्री महेश चन्द्र थवाल - कमांडेंट
- श्री डी जयचंद्र नायडू - निरीक्षक

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

- श्री मंथीर एक्का - महानिरीक्षक
- श्री निशित चंद्र - उप महानिरीक्षक
- श्री मोहन सिंह — निरीक्षक

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)

- श्री राकेश शर्मा — ग्रुप कमांडर

सशस्त्र सीमा बल (SSB)

- श्री मलोथु रामुलु नाडक - महानिरीक्षक
- श्री संजय बहादुर चंद - कमांडेंट

गृह मंत्रालय (MHA)

- श्री नारायणमूर्ति वेंकटरामनन - उप विदेशी भाषा सलाहकार
- श्री उज्जवल कुमार शुक्ला - संयुक्त उप निदेशक/कार्यकारी
- श्री जिजो जैकब — सहायक निदेशक/कार्यकारी
- श्री मोहम्मद जफारे आलम — सहायक निदेशक/कार्यकारी
- श्री रमन कुमार — सहायक निदेशक/कार्यकारी
- श्री कमलकांत — सहायक निदेशक/स्टाफ अधिकारी
- सुश्री फुल माया तमांग - सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी-I/EXE
- श्री खोटा एबल शिंगलाई — सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी-I/कार्यकारी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

- श्रीमती शोभा दत्ता - पुलिस अधीक्षक
- श्री मनोज बनर्जी - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
- श्रीमती गिन्नी राणा - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
- श्री रमेश चंद — सहायक उप-निरीक्षक
- श्री मदन लाल धीमान - सहायक उप निरीक्षक
- श्री संजय कुमार सामल - पुलिस उपाधीक्षक

विशेष सुरक्षा समूह (SPG)

- श्री उमेश चंद्र दत्ता - महानिरीक्षक
- राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)
- श्री गंभीर सिंह चौहान - उप महानिरीक्षक

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)

- श्री के.एम. मल्लिकार्जुन प्रसन्ना - महानिरीक्षक
- श्री ब्रज भूषण पाठक - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

रक्षा उत्पादन विभाग

- श्री साजिद फरीद शापू - अतिरिक्त महानिदेशक

रेलवे सुरक्षा बल (RPF)

- श्री राजेश लाल — सहायक सुरक्षा आयुक्त

अग्निशामक सेवा

गोवा

- श्री राजेंद्र अनंत हल्दनकर - उप निदेशक (अग्निशमन सेवाएँ)

ओडिशा

- श्री मलाया कुमार मोहंती — सहायक स्टेशन अधिकारी

उत्तर प्रदेश

- श्री नईमुद्दीन - अग्रणी अग्निशामक

CISF

- श्री महेंद्र सिंह कंडारी - सहायक कमांडेंट

होम गार्ड्स और नागरिक सुरक्षा सेवा

छत्तीसगढ़

- श्री राजेश कुमार पांडे - अतिरिक्त कमांडेंट जनरल

दिल्ली NCT

- श्री सुरेश कुमार शौकीन - कमांडेंट

हिमाचल प्रदेश

- श्री प्रेम राज — कंपनी कमांडर

सुधार सेवाएँ

महाराष्ट्र

- श्री संजीव सखाराम घाणेकर - सुभेदार
- श्री संजय राजारामजी तलवारे - हवलदार

राष्ट्रीय मामले

- अमित शाह ने मुंबई में 'सहकार नव-क्रांति' कार्यक्रम के तहत शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए 'बैंक इन ए बॉक्स' और एक समर्पित सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) का शुभारंभ किया है। यह एकीकृत प्लेटफॉर्म कोर बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, नियामक अनुपालन, ऋण वितरण, आधार-आधारित सेवाएं और एआई-आधारित धोखाधड़ी रोकथाम जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। एसओसी 24x7 साइबर सुरक्षा निगरानी प्रदान करेगा, जबकि म्यूलहंटर संदिग्ध लेनदेन और अवैध खातों की पहचान करने में मदद करेगा। NUCFDC में लगभग ₹306 करोड़ का निवेश किया गया है और लगभग 650 यूसीबी पहले ही इससे जुड़ चुके हैं। NFSU के साथ एक समझौता जापान साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और डिजिटल फोरेंसिक में सहयोग प्रदान करेगा।
- भारत ने 8 अगस्त 2026 को ई-समुद्र का शुभारंभ किया, जो एक व्यापक डिजिटल समुद्री शासन मंच है और नाविकों, शिपिंग कंपनियों, बंदरगाहों और अन्य हितधारकों को एकल-खिड़की सेवाएं प्रदान करता है। यह मंच डिजिटल प्रथम और फेसलेस गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन भुगतान, रियल टाइम ट्रेकिंग, डिजिटल प्रमाणपत्र और सुव्यवस्थित कार्यप्रवाह की सुविधा प्रदान करता है। सहायक पहलों में 24x7 ई-नाविक शिकायत निवारण, प्रस्तावित नाविक ट्रेकिंग डैशबोर्ड, डिजिटल नाविक रोजगार समझौता (d-SEA) और उन्नत कल्याणकारी उपाय शामिल हैं। भारत में सक्रिय नाविकों की संख्या 2013 में 1.03 लाख से बढ़कर 2025 में 3.23 लाख से अधिक हो गई है, जिससे भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बन गया है। यह पहल मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 का समर्थन करती है।

- NeGD ने MeitY के नेतृत्व में, एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया (AAERI) के साथ ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए एक डिजिटल प्रमाणीकरण प्लेटफॉर्म, AAERI वेरिफाई लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। 7 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में AAERI के वार्षिक सम्मेलन में लॉन्च किया गया यह प्लेटफॉर्म, शैक्षणिक, पहचान और वित्तीय दस्तावेजों के सुरक्षित, कागजरहित और सहमति-आधारित सत्यापन के लिए डिजिटलॉकर के साथ एकीकृत है। इसकी दो-चरणीय प्रणाली आवेदन से पहले छात्र के प्रमाण पत्रों और प्रवेश प्रस्ताव के बाद प्रायोजक के वित्त का सत्यापन करती है। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित रिकॉर्ड अधिकृत संस्थानों से सीधे साझा किए जा सकते हैं, जिससे कागजी कार्रवाई, मैन्युअल सत्यापन और धोखाधड़ी के जोखिम कम होते हैं, साथ ही अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में तेजी आती है और दस्तावेजों की प्रामाणिकता मजबूत होती है।
- उप-राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अगस्त क्रांति दिवस और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में 9 अगस्त 2026 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने श्री विजयपुरम स्थित ध्वज बिंदु पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और द्वीप समूह के भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सेलुलर जेल से संबंध को रेखांकित किया। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में ऐतिहासिक तिरंगा फहराने की घटना को याद किया गया। राधाकृष्णन ने नागरिकों से एकता, देशभक्ति और सामूहिक जिम्मेदारी को बनाए रखने का आग्रह किया और साथ ही ग्रेट निकोबार विकास परियोजना, संपर्क, समुद्री क्षमताओं और पर्यावरण संरक्षण पर प्रकाश डाला।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 31 जुलाई 2026 तक भारत ने 300.50 गीगावाट स्थापित गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का मील का पत्थर पार कर लिया है। सौर ऊर्जा 164.59 गीगावाट के साथ सबसे आगे रही, इसके बाद पवन ऊर्जा 58.14 गीगावाट, जलविद्युत 57.24 गीगावाट, जैव-ऊर्जा 11.75 गीगावाट और परमाणु ऊर्जा 8.78 गीगावाट रही। कुल स्थापित क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा अब 54% से अधिक है, जबकि कुल क्षमता लगभग 552 गीगावाट है। भारत ने 2025-26 के दौरान रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता जोड़ी। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन 2014-15 में 190.96 BU से बढ़कर 2025-26 में 477.79 BU हो गया, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सहायक है।
- केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) भारत का प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण और निगरानी के लिए बनाया गया है। DARPG द्वारा विकसित यह प्रणाली नागरिकों को केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक एकीकृत मंच के माध्यम से जोड़ती है। नागरिकों को ऑनलाइन ट्रेकिंग के लिए एक विशिष्ट पंजीकरण आईडी प्राप्त होती है। CPGRAMS चौबीसों घंटे सातों दिन (24x7) कार्यरत रहता है, अंग्रेजी के अलावा 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है और "एक राष्ट्र-एक पोर्टल" दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इस प्रणाली के तहत शिकायतों का समाधान अधिकतम 21 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत होती है। शिकायत निवारण से असंतुष्ट नागरिकों के लिए अपील तंत्र एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायी शासन को बढ़ावा मिलता है।
- भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई, जो 368 शेरों की वृद्धि या लगभग 70% की बढ़ोतरी दर्शाती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व शेर दिवस 2026 के अवसर पर इस उपलब्धि को उजागर करते हुए वन अधिकारियों, संरक्षणवादियों और स्थानीय समुदायों को इसका श्रेय दिया। इस प्रजाति का भौगोलिक क्षेत्र 2020 में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में घोषित 'प्रोजेक्ट लॉयन' के तहत पर्यावास सुधार, रोग निगरानी, पशु चिकित्सा देखभाल, वैज्ञानिक जनसंख्या आकलन, प्रौद्योगिकी आधारित संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। गुजरात का ग्रेटर गिर भारत में एशियाई शेरों का प्रमुख प्राकृतिक पर्यावास क्षेत्र बना हुआ है।
- भारत 15 अगस्त 2026 को अपना 80वाँ स्वतंत्रता दिवस "युवा शक्ति: विकसित भारत@2047 की यात्रा का नेतृत्व" विषय के साथ मनाएगा। यह विषय 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा भारतीयों के योगदान को रेखांकित करता है। लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने का अवसर भी मनाया जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' को लाल किले की प्राचीर से प्रस्तुत किया जाएगा। समारोह में लगभग 5,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड के 19 पदक विजेता भी शामिल हैं। लगभग 2,500 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) कैडेट और मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भी इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का नेतृत्व करेंगे और इस अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
- 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले में आयोजित कार्यक्रम में पहली बार 'वंदे मातरम्' को आधिकारिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर पहुँचेंगे और इसके बाद उपस्थित लोग खड़े होकर राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' सुनेंगे। इसके पश्चात वे राष्ट्रीय ध्वज फहराएँगे, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वंदे मातरम्' भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहरा संबंध रहा है। वर्ष 2026 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में 'युवा शक्ति' पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें शिक्षा, नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, खेल और राष्ट्र-निर्माण के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को रेखांकित किया जाएगा। समारोह में विपक्ष के नेता को भी आमंत्रित किया गया है।
- भारत में एशियाई सिंहों की संख्या वर्ष 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। इस प्रकार, सिंहों की संख्या में 368 की वृद्धि हुई है, जो लगभग 70% है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि का श्रेय वन अधिकारियों, संरक्षणवादियों और स्थानीय समुदायों के प्रयासों को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2020 में शुरू की गई 'प्रोजेक्ट लायन' का उद्देश्य रोगों की निगरानी, आवास प्रबंधन, पशु चिकित्सा देखभाल, वैज्ञानिक निगरानी, प्रौद्योगिकी आधारित संरक्षण तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना है। सिंहों का भौगोलिक क्षेत्र वर्ष 2020 में लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर अब लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। गुजरात का ग्रेटर गिर क्षेत्र अभी भी एशियाई सिंहों का प्रमुख आवास बना हुआ है। आवास क्षेत्रों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी सिंहों के दीर्घकालिक संरक्षण को और मजबूत कर रही है।

- त्रिपुरा ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार सरसों के फूलों से प्राप्त शहद की खेप दुबई भेजी। 1 मीट्रिक टन की इस खेप का निर्यात डेरगांग किसान उत्पादक संगठन (FPO) द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEEDA) की सहायता से किया गया। सॉल्ट रेंज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और निर्यातोन्मुख आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में FPO को सहयोग प्रदान किया। इस पहल से मधुमक्खी पालकों और किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक बेहतर पहुँच मिलने, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने तथा किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होने की उम्मीद है। कृषि मंत्री रतन लाल नाथ ने मधुमक्खी पालन (एपीकल्चर) और जैविक कृषि के महत्व पर जोर दिया। यह निर्यात संगठित किसान समूहों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच बनाने की क्षमता को दर्शाता है।
- भारत ने वन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन को मजबूत करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के माध्यम से 45 प्रमुख आक्रामक विदेशी पादप प्रजातियों की पहचान की है। ये आक्रामक पौधे जल, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश और स्थान के लिए स्थानीय वनस्पतियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। इससे जैव विविधता और पारिस्थितिक प्रक्रियाएँ प्रभावित होती हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) ने राज्यवार सूची तैयार की है, जिसमें वन और गैर-वन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रबंधन योजना विकसित करना है। इन आक्रामक प्रजातियों को हटाने और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की है। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2023 आक्रामक प्रजातियों के नियंत्रण, क्षरित भूमि के पुनर्स्थापन तथा देशज और स्थानीय प्रजातियों के माध्यम से वनस्पतियों के पुनर्जनन को बढ़ावा देती है।
- लोकसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया है। इसमें न्यायाधिकरणों की नियुक्तियों, प्रशासन और कार्य-प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित पाँच सदस्यीय आयोग में एक अध्यक्ष, दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। यह विधेयक न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का स्थान लेने और न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता तथा प्रशासन से संबंधित चिंताओं का समाधान करने के उद्देश्य से लाया गया है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) के अंतर्गत 16 न्यायाधिकरण आएँगे। इनमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT), सशस्त्र बल अधिकरण (AFT) और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) शामिल हैं। इस विधेयक को लागू करने की अनुमानित लागत ₹27.14 करोड़ है। न्यायाधिकरणों की व्यवस्था का संवैधानिक आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B में दिया गया है।
- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का उपयोग करते हुए कृषि विद्यार्थियों के लिए नई छात्रवृत्ति और फेलोशिप भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया। ICAR-IARI, पूसा में 6,000 से अधिक कृषि विद्यार्थियों को ₹21.35 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। पात्र विद्यार्थियों को हर महीने छात्रवृत्ति की सहायता राशि प्राप्त होगी। इससे भुगतान में होने वाली देरी कम होगी और पारदर्शिता में

सुधार होगा। शिवराज सिंह चौहान ने व्यावहारिक कृषि शिक्षा, खेतों में अनुभव, नवाचार, स्टार्टअप और अनुसंधान पर जोर दिया। इस पहल का उद्देश्य कृषि शिक्षा को मजबूत करना, किसानों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करना तथा खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसानों की आय में वृद्धि से जुड़े राष्ट्रीय उद्देश्यों को समर्थन प्रदान करना है।

- तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित वी. ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण (वीओसी पत्तन) ने 10 अगस्त 2026 को स्कोप-2 उत्सर्जन-मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रमुख पत्तन बनने की उपलब्धि हासिल की। स्वतंत्र सत्यापन में पुष्टि की गई कि संबंधित अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा से होने वाला विद्युत उत्पादन, विद्युत की कुल खपत से अधिक था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पत्तन की कुल विद्युत खपत का 93.89% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हुआ। यह पत्तन ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 50001:2018 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रमुख पत्तन भी बना। वर्तमान में पत्तन के पास 7.04 मेगावाट सौर ऊर्जा और 2 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है। भविष्य में अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता, 17 मेगावाट पवन ऊर्जा, बैटरी भंडारण प्रणाली और हरित हाइड्रोजन केंद्र विकसित करने की योजना है। इन पहलों से भारत के हरित पत्तन विकास और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
- वर्ष 2026 में भारत ने यूरिया आयात के स्रोतों में विविधता लाई, क्योंकि पश्चिम एशिया से संबंधित आपूर्ति बाधाओं के कारण उर्वरकों की उपलब्धता प्रभावित हुई। अप्रैल से जून के बीच भारत ने 17 देशों से 15.08 लाख टन यूरिया आयात किया। इसमें से 52% यूरिया मिश्र, अल्जीरिया, नाइजीरिया और जॉर्जिया से प्राप्त हुआ। केवल जून माह में भारत ने मिश्र से 3.95 लाख टन यूरिया आयात किया। इसके अलावा अल्जीरिया, नाइजीरिया और जॉर्जिया से भी बड़ी मात्रा में यूरिया आयात किया गया। वर्ष 2025-26 में आयातित यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी का व्यय 128.4% बढ़कर ₹47,956.24 करोड़ हो गया। भारत ने उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हॉर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से भी यूरिया की आपूर्ति की तथा 25 लाख टन यूरिया के आयात के लिए निविदा को अंतिम रूप दिया। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों के लिए उर्वरकों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना और वैश्विक आपूर्ति में आने वाली बाधाओं के प्रभाव को कम करना है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME मंत्रालय) और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने 5 अगस्त 2026 को भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों के लिए बाजार तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। GI उत्पादों के उत्पादकों और अधिकृत उपयोगकर्ताओं को 'भारत GI' नाम के अंतर्गत ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) और सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर जोड़ा जाएगा। इस साझेदारी के तहत GI उत्पादों को 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) पारिस्थितिकी तंत्र से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और खरीदार-विक्रेता बैठकों में GI उत्पादों के लिए विशेष मंडप स्थापित करने में सहायता दी जाएगी। गुणवत्ता मानकीकरण, क्षमता निर्माण और डिजिटल सशक्तीकरण जैसे उपायों से कारीगरों और पारंपरिक उत्पादकों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक व्यापक पहुँच बनाने में मदद मिलेगी। इस पहल से GI उत्पादों की पहचान, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और आय के अवसरों में वृद्धि होने की उम्मीद है।

- विश्व हाथी दिवस 2026 के अवसर पर एशियाई हाथियों के संरक्षण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। भारत में विश्व की लगभग 60% जंगली एशियाई हाथी आबादी पाई जाती है। एसएआईईई 2021-25 के अनुमान के अनुसार, भारत में 22,446 हाथी हैं। इनके संरक्षण के लिए 33 हाथी अभयारण्य और 150 चिन्हित हाथी गलियारे बनाए गए हैं। हाथी परियोजना के माध्यम से हाथियों के आवास संरक्षण, मानव-हाथी संघर्ष को कम करने और बंदी हाथियों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है। संरक्षण के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी, रेडियो कॉलर, आनुवंशिक डेटाबेस और पूर्व चेतावनी प्रणालियों जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। भारत ने पहली बार डीएनए आधारित समकालिक हाथी गणना भी की। रेलवे द्वारा किए गए सुरक्षा उपायों से ट्रेन की चपेट में आने से हाथियों की मृत्यु की संख्या वर्ष 2013 में 26 से घटकर 2024 में 12 हो गई है।
- संसद ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, 2026 पारित किया है। इसमें प्रमुख न्यायाधिकरणों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। आयोग न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों, प्रशासन, जाँच और कार्य-प्रदर्शन की निगरानी करेगा। साथ ही, यह राष्ट्रीय न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड का रखरखाव भी करेगा। यह विधेयक 16 न्यायाधिकरणों पर लागू होगा। इनमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT), सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (CESTAT), ऋण वसूली अधिकरण (DRT) और दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकरण (TDSAT) शामिल हैं। न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों का कार्यकाल पाँच वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रहेगा। वहीं सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रहेगा। इस सुधार का उद्देश्य न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करना और न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाना है।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने नदी गंगा प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2026 के माध्यम से गंगा के बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन की रूपरेखा में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत बाढ़ मैदानों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है—सक्रिय बाढ़ क्षेत्र, विनियामक क्षेत्र और चेतावनी क्षेत्र। सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में वे क्षेत्र शामिल हैं, जो पाँच वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इस क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। विनियामक क्षेत्र में वे क्षेत्र शामिल हैं, जहाँ 5 से 25 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ का खतरा रहता है। वहीं चेतावनी क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र शामिल हैं, जो 25 से 100 वर्ष में एक बार आने वाली बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं। इन बाढ़ के दोनों क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना आवश्यक होगा। इन प्रावधानों का उद्देश्य बाढ़ के जोखिम का प्रभावी प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे नियंत्रित एवं नियोजित विकास को मजबूत करना है।
- भारतीय रेलवे द्वारा 1 जुलाई 2025 को शुरू किए गए रेलवन अनुप्रयोग को 2 अगस्त 2026 तक 4.76 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस अनुप्रयोग के माध्यम से प्रतिदिन औसतन लगभग 10 लाख टिकट बुकिंग की जाती है। इनमें लगभग 2.79 लाख आरक्षित और 7.24 लाख अनारक्षित टिकट शामिल हैं। राष्ट्रीय रेल पृष्ठताछ प्रणाली (NTES) प्रतिदिन 6 करोड़ से अधिक पृष्ठताछ का प्रबंधन करती है और इसमें एक समय में लगभग 80,000 उपयोगकर्ता सक्रिय रहते हैं। इसके एंड्रॉयड और आईओएस अनुप्रयोगों को क्रमशः 4.5 करोड़ से अधिक और 16 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं, जबकि लगभग 39% अनारक्षित टिकटों की बुकिंग अब डिजिटल माध्यम से की जा रही है।
- संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को संपन्न हुआ। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की अनिश्चितकाल के लिए स्थगित (सत्रावसान) कर दिया गया। संसद ने 11 विधेयक पारित किए, जबकि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक लंबित रहा। नीट-यूजी विवाद, कथित पुलिस कार्रवाई और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर विपक्ष के विरोध-प्रदर्शनों के कारण संसद की कार्यवाही बार-बार बाधित हुई। सत्र के दौरान पारित प्रमुख विधेयकों में सार्वजनिक परीक्षाओं, राष्ट्रीय सम्मान, जन्म और मृत्यु, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), कराधान, बैंकर्स बुक्स, न्यायाधिकरणों, केरल के नाम, सहकारिता और खनिजों से संबंधित विधेयक शामिल थे। लोकसभा की अंतिम बैठक की शुरुआत 'वंदे मातरम्' की छह कड़ियों के गायन के साथ हुई, जबकि राज्यसभा ने खान और खनिज संशोधन विधेयक पारित किया।
- खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को 13 अगस्त 2026 को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया। इस विधेयक के माध्यम से खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन किया गया है। विधेयक में खनिज-युक्त भूमि के विनियमन पर केंद्र सरकार के अधिक नियंत्रण का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, राज्यों को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना खनिज अधिकारों पर कर, उपकर या अन्य शुल्क लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। राज्यों द्वारा पहले लगाए गए कुछ ऐसे खनिज कर, जिनकी अभी तक वसूली नहीं हुई है, उन्हें अमान्य माना जाएगा और इसके लिए पहले से वसूली गई राशि वापस करना आवश्यक नहीं होगा। मौजूदा खनन पट्टाधारक बिना अतिरिक्त भुगतान के लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, सोना और चाँदी जैसे खनिजों को अपने पट्टे में शामिल कर सकेंगे। इस कानून में कैप्टिव खदानों से खनिजों की बिक्री पर लगी सीमा को भी समाप्त किया गया है। इससे खनिज अन्वेषण और रणनीतिक खनिज संसाधनों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- 31 जुलाई 2026 तक, डिजिलॉकर पर 72.43 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता थे, जबकि उमंग के उपयोगकर्ताओं की संख्या 11.66 करोड़ से अधिक हो गई। यह भारत में डिजिटल इंडिया पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार को दर्शाता है। पिछले तीन वर्षों में डिजिलॉकर पर लगभग 72.86 करोड़ दस्तावेज़ प्राप्त करने से संबंधित लेन-देन दर्ज किए गए। इस मंच पर 5,437 प्रकार के दस्तावेज़ और सेवाएँ उपलब्ध थीं। इसी अवधि में उमंग पर लगभग 798 करोड़ लेन-देन दर्ज किए गए और इसके माध्यम से 2,575 सक्रिय सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही थीं। इस बीच, 30 जून 2026 तक ग्राम पंचायत स्तर पर 4,07,122 सामान्य सेवा केंद्र (CSC) कार्यरत थे। इनमें से 70,069 केंद्र महिला ग्राम स्तरीय उद्यमियों द्वारा संचालित किए जा रहे थे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2015 में की गई थी।

- संसद ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जिससे केरल का आधिकारिक नाम बदलकर 'केरलम्' किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दी, जिसके बाद राज्यसभा ने भी ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया। यह कदम 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के बाद उठाया गया है, जिसमें राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया गया था। इस विधेयक में संविधान की प्रथम अनुसूची और संबंधित प्रावधानों में आवश्यक संशोधन का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक प्रक्रिया का आधार अनुच्छेद 3 है, जो राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित है। यह नाम परिवर्तन राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद प्रभावी होगा।
- लोकसभा ने 12 अगस्त 2026 को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे। समिति को अपनी रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह तक प्रस्तुत करनी होगी। यह निर्णय विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन और विधेयक को वापस लेने की मांग के बीच लिया गया। विपक्षी नेताओं ने विधेयक के अल्पसंख्यकों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की, जबकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। 25 मार्च 2026 को प्रस्तुत इस विधेयक में विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की निगरानी को अधिक कठोर बनाने तथा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) का लाइसेंस रद्द होने के बाद उनकी परिसंपत्तियों के प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने हिमालयी वनाग्नि पर अपनी 412वीं रिपोर्ट में राष्ट्रीय चीड़-पत्ती उपयोग नीति बनाने की सिफारिश की है। समिति ने वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, सूखी चीड़ की जैविक सामग्री के संग्रह के लिए प्रोत्साहन तथा हिमालयी जैवभार प्रबंधन रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव दिया है। समिति ने हिमालयी पिरूल प्रबंधन मिशन शुरू करने, चीड़ की सूखी पत्तियों के लिए ₹3-4 प्रति किलोग्राम का न्यूनतम खरीद मूल्य निर्धारित करने तथा राष्ट्रीय या क्षेत्रीय चीड़-पत्ती प्रबंधन बोर्ड के गठन का सुझाव दिया है। प्रसंस्कृत चीड़ की पत्तियों से बने छरों (पैलेट) का ऊर्जा मूल्य लगभग 5,500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ सह-दहन के लिए किया जा सकता है। समिति ने उपग्रह आधारित निगरानी तथा हिमालयी क्षेत्रों में क्षेत्रीय राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) केंद्रों की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया है।
- नई दिल्ली के जनपथ स्थित पुनर्निर्मित हथकरघा हाट को हथकरघा अनुभव केंद्र में परिवर्तित किया गया है। यह केंद्र भारत की हथकरघा विरासत को आधुनिक डिजाइन, उद्यमिता और खुदरा व्यापार से जोड़ता है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा इसका उद्घाटन 14 अगस्त 2026 को किया जाना निर्धारित था। उद्घाटन प्रदर्शनी में 24 पुरस्कार विजेता बुनकर तथा 'बीव द फ्यूचर 5.0' के अंतर्गत 30 से अधिक चयनित ब्रांड शामिल हैं। भूतल पर 'ओडिशा के हथकरघा वस्त्रों का पुनर्कल्पन' विषय पर प्रदर्शनी लगाई गई है, जबकि प्रथम तल पर स्थायी 'विश्वकर्मा दीर्घा' बनाई गई है, जिसमें दुर्लभ वस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। द्वितीय तल पर डिजाइन सम्मेलन और वन से प्रेरित एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें भारतीय हथकरघा वस्त्रों में प्राकृतिक आकृतियों और रूपांकनों को प्रदर्शित किया गया है।
- अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर 13 अगस्त 2026 को महाराष्ट्र के नांदेड के पास स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी मुगत में कृपाण से हमला किया गया, जिसमें वे घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, लगभग दोपहर 1:45 बजे एक निहंग सदस्य ने बादल पर हमला किया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनके दाहिने हाथ पर दो से तीन टाँके लगाए गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। बादल की सुरक्षा करते समय सुरक्षा अधिकारी संतोष केंद्रे भी घायल हो गए। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेताओं ने इस घटना को खुफिया तंत्र की विफलता बताया और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जाँच कराने की मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जाँच के आदेश दिए और सुखबीर सिंह बादल से बातचीत की। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल ने तख्त श्री हजूर साहिब का दौरा किया था।
- नीति आयोग ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की क्षमता वाले चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें रसायन, वस्त्र, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग उपकरण तथा सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण शामिल हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में इन क्षेत्रों की बाजार क्षमता, बुनियादी ढाँचा, नीतिगत समर्थन, कच्चा माल, प्रौद्योगिकी, रोजगार और वैश्विक मूल्य शृंखला में एकीकरण का आकलन किया गया है। रसायन क्षेत्र में उत्पादों के आगे के चरणों में अधिक मूल्य संवर्धन तथा कच्चे माल के रूप में उपयोग होने वाले पदार्थों के कुशल उपयोग की आवश्यकता है। वस्त्र क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2%, विनिर्माण के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में 11% और वस्तु निर्यात में 9% का योगदान देता है। इस क्षेत्र को बेहतर बुनियादी ढाँचे, कौशल और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण में स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है, जबकि सौर फोटोवोल्टिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता के ऊपरी चरणों को मजबूत करने, अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा प्रौद्योगिकी साझेदारी की आवश्यकता है। नीति आयोग आठ अन्य क्षेत्रों की भी समीक्षा करेगा।
- रेलवे बोर्ड ने अगस्त 2026 में लंबी दूरी की अंतरराज्यीय रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सात नई अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाओं को मंजूरी दी। इन ट्रेनों के प्रमुख मार्ग हैं—गोरखपुर-दिल्ली, गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस, धनबाद-कोयंबटूर, चारलापल्ली-गोरखपुर, प्रयागराज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस, प्रयागराज-उधना और सुबेदारगंज-लोकमान्य तिलक टर्मिनस। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना और गुजरात के प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़ेंगी। कोटा, रतलाम, वडोदरा, नागपुर और विजयवाड़ा सहित कई महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शनों को इन सेवाओं से कनेक्टिविटी मिलेगी। तेलंगाना के मंचेरियल और पेद्दापल्ली को कुछ चयनित सेवाओं में ठहराव प्रदान किया गया है। गोरखपुर-दिल्ली विशेष ट्रेन को 10 अगस्त 2026 से नियमित साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा में परिवर्तित कर दिया गया।

- केंद्र सरकार ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी गलियारे में मालदा-न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड पर चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी दी है। इसे आमतौर पर 'चिकन नेक' के नाम से जाना जाता है। यह संकीर्ण गलियारा मुख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों से जोड़ता है। अपने सबसे संकरे स्थान पर इसकी चौड़ाई लगभग 20-22 किलोमीटर है। इस विस्तार परियोजना में चौथी रेल लाइन, तिनमाई घाट और बागडोगरा के बीच लगभग 29 किलोमीटर लंबी भूमिगत दोहरी रेल लाइन तथा बारसोई में चल रहा रेल लाइन दोहरीकरण कार्य शामिल है। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य अप्रैल 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है। यह परियोजना यात्री और माल परिवहन, पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स तथा रणनीतिक रक्षा आवागमन को मजबूत करेगी।
- लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, जिसकी गाड़ी संख्या 82501 और 82502 है, वाणिज्यिक ब्रांडिंग व्यवस्था के तहत 'स्पाइट तेजस एक्सप्रेस' के नाम से संचालित होगी। कोका-कोला के एक ब्रांड स्पाइट ने इस ट्रेन के ब्रांडिंग और विज्ञापन अधिकार प्राप्त किए हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत ट्रेन के बाहरी हिस्से पर विनाइल आवरण तथा आंतरिक हिस्से में विज्ञापन लगाए जा सकेंगे। इससे रेलवे को किराया रहित अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ब्रांडिंग और यात्री सेवाओं का प्रबंधन करेगा, जबकि भारतीय रेल रेलवे अवसंरचना का स्वामित्व बनाए रखेगा और निर्धारित दुलाई शुल्क प्राप्त करेगा। रेलवे अधिकारियों ने स्टेशनों को ट्रेन की घोषणा उसके नए ब्रांड नाम से करने के निर्देश दिए हैं। ब्रांडिंग की अवधि 19 अगस्त से 11 नवंबर 2026 तक निर्धारित की गई है, हालांकि विभिन्न रिपोर्टों में अनुबंध की अवधि को लेकर अलग-अलग जानकारी दी गई है।
- केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 से अब तक 18 स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची से हटा दिया है। इन स्मारकों को सूची से हटाए जाने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में अब 3,688 केंद्रीय संरक्षित स्मारक और स्थल हैं। इन स्मारकों का संरक्षण प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत ऐसे स्मारकों को केंद्रीय संरक्षण सूची से हटाया जा सकता है, जो अब राष्ट्रीय महत्व के नहीं रह गए हैं। 8 मार्च 2024 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इन 18 स्मारकों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इन स्मारकों में निकोलसन की प्रतिमा, कोस मीनार संख्या 13, बड़ा खंभा कब्रिस्तान, गनर बर्किल की कब्र तथा तेलिया नाला के बौद्ध अवशेष शामिल हैं। भारत ने जून 2026 तक विदेशों से 662 ऐतिहासिक कलाकृतियाँ भी वापस प्राप्त की हैं।

राज्यों से संबंधित प्रमुख समाचार

- तमिलनाडु विधानसभा ने 10 अगस्त 2026 को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत 'तमिल थाई वाइथु' को राज्य में आयोजित होने वाले सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में प्रथम गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यह नियम सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) तथा अन्य सार्वजनिक संगठनों पर लागू होगा। यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तुत किया गया और ध्वनिमत से पारित किया गया।

प्रस्ताव को DMK, AIADMK, कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों का समर्थन मिला। यह निर्णय 'तमिल थाई वाइथु', 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान के क्रम को लेकर हुए विवाद के बाद लिया गया। 'तमिल थाई वाइथु', मनोन्मणियम सुंदरनार द्वारा रचित 'मनोन्मणियम' से लिया गया है। इसे वर्ष 2021 में तमिलनाडु के राज्य गीत के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था।

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त 2026 को पुडुचेरी पुलिस को प्रतिष्ठित 'राष्ट्रपति पुलिस ध्वज' प्रदान किया। यह सम्मान पुलिस बल की बहादुरी, समर्पण और सेवा के लिए दिया गया। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन. रंगासामी भी उपस्थित रहे। अमित शाह ने भौगोलिक रूप से अलग-अलग चार क्षेत्रों में पुडुचेरी पुलिस की जिम्मेदारियों को रेखांकित किया। उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान पुलिस बल की अग्रिम पंक्ति में निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने भारत के तीन नए आपराधिक कानूनों पर भी चर्चा की और प्रौद्योगिकी, समयबद्धता तथा विश्वास के महत्व पर जोर दिया। प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में ₹2,200 करोड़ की NH-332A को चार लेन में बदलने की परियोजना तथा रनवे के विस्तार को शामिल किया गया। वर्ष 2014 से 2026 के बीच पुडुचेरी को लगभग ₹13,762 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, लगभग ₹39,000 करोड़ का औद्योगिक निवेश भी हुआ।
- असम ने 7 अगस्त 2026 को सोनितपुर जिले के सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य में नए कलामाटी वन्यजीव रेंज कार्यालय का उद्घाटन किया। इस नए कार्यालय से वन प्रशासन, गश्त, आवास संरक्षण, वन्यजीव निगरानी तथा संरक्षण गतिविधियों को मजबूत करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। यह अभयारण्य लगभग 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 175 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र (कोर एरिया) शामिल है। यह असम की हिमालय की तलहटी में स्थित है। यहाँ के वन, घासभूमि और नदी तंत्र एशियाई हाथी, भारतीय गौर, गैंडा, तेंदुआ, बाघ तथा अनेक पक्षी प्रजातियों के लिए अनुकूल आवास प्रदान करते हैं। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य विशेष रूप से संकटग्रस्त सफेद पंखों वाली बत्तख के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह पक्षी असम का राज्य पक्षी है। नया कार्यालय क्षेत्रीय समन्वय को बेहतर बनाने तथा जैव विविधता के संरक्षण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- गुजरात वन विभाग ने 11 अगस्त 2026 को नलसरोवर पक्षी अभयारण्य के आसपास ₹2.94 करोड़ की प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की। नलसरोवर एक रामसर-मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि है। यह पहल गुजरात की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना परियोजना से जुड़ी है। इसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) का सहयोग प्राप्त है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर उत्पन्न करना है। विरमगाम तालुका के कायला गाँव में एक संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर जिलों के विभिन्न गाँवों को शामिल किया गया है। पारिस्थितिकी विकास समितियाँ स्थानीय 'स्वच्छता प्रहरियों' की नियुक्ति करेंगी, जो सूखे प्लास्टिक कचरे का संग्रह और पृथक्करण करेंगी। यह परियोजना आर्द्रभूमि संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी और आजीविका सृजन को एकीकृत करती है।

- जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 9 अगस्त 2026 को डोडा जिले के भद्रवाह में स्थित रतनगढ़ किले के जीर्णोद्धार के लिए ₹10 करोड़ की राशि मंजूर की। इस किले का निर्माण 1733 में राजा संपत पाल ने करवाया था। इसे भद्रवाह घाटी में निर्मित सात मूल बुर्जों में से एकमात्र सुरक्षित बची संरचना बताया जाता है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, बाद में इस किले का उपयोग कारागार के रूप में भी किया गया था। जीर्णोद्धार का उद्देश्य किले की वास्तुकला और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करना तथा इसे चिनाब घाटी में पर्यटन और विरासत स्थल के रूप में विकसित करना है। चिनाब घाटी में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र अपने पर्वतीय भू-दृश्यों, नदी घाटियों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, जिससे रतनगढ़ किले की पर्यटन क्षमता और बढ़ जाती है।
- कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख करते हुए उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मोटरसाइकिलों को परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत करने और उन्हें बाइक टैक्सी के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गई थी। राज्य सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा, बीमा कवरेज, सड़क पर भीड़, प्रदूषण और नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं। यह विवाद 23 जनवरी 2026 के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सामने आया, जिसमें ओला, उबर, रैपिडो, मोटरसाइकिल मालिकों और बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन से संबंधित मामला शामिल था। कर्नाटक सरकार का तर्क है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 मोटरसाइकिलों को स्वतः वाणिज्यिक टैक्सी के रूप में संचालित करने की अनुमति नहीं देता है। 18 मार्च 2026 को राज्यसभा में दिए गए उत्तर में भी कहा गया कि मोटर वाहन अधिनियम या संबंधित नियमों के तहत 'बाइक टैक्सी' को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इससे बाइक टैक्सी के नियमन को लेकर बहस और तेज हो गई है।
- कर्नाटक ने 12 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में Tathyakosh.in का शुभारंभ किया। यह सार्वजनिक डेटा की खोज के लिए एक खुला और गैर-वाणिज्यिक डिजिटल सार्वजनिक संसाधन है। इसे ACSEL Technology Forum, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सरकार का उत्कृष्टता केंद्र है, ने IIT Alumni Centre Bengaluru के सहयोग से विकसित किया है। यह मंच 458 सार्वजनिक डेटा रिपॉजिटरी से 15 लाख से अधिक डेटासेट को एक साथ उपलब्ध कराता है। यह मौजूदा डेटाबेस को बदलने के बजाय एक डेटा खोज मंच के रूप में कार्य करता है। स्टार्टअप, शोधकर्ता और प्रौद्योगिकी से जुड़ी टीमों इसके माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य सेवा, जलवायु, कानूनी अनुसंधान और वित्तीय समावेशन से संबंधित जानकारी खोज सकती हैं। Tathyakosh नाम संस्कृत के शब्दों से प्रेरित है, जिसमें 'तथ्य' का अर्थ Fact (तथ्य) और 'कोश' का अर्थ Repository (भंडार) है।
- उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2026 में उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। अंतिम कार्यकारी आदेश में नए परिसर के लिए हल्द्वानी-रूद्रपुर राजमार्ग के किनारे लामाचौड़ में 30 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले कहा था कि किसी उच्च न्यायालय की स्थापना या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना एक प्रशासनिक निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय के 16 जुलाई के निर्देश के बाद मंत्रिमंडल ने 7 अगस्त को वन भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी। हालाँकि, एक जनहित याचिका (PIL) में पर्यावरण संबंधी चिंताएँ उठाई गई हैं। याचिका में दावा किया गया है कि प्रस्तावित स्थल आरक्षित वन क्षेत्र और हाथियों के गलियारे में स्थित है। इस परियोजना को लेकर हजारों पौधों को हटाए जाने की आशंका सहित अन्य पर्यावरणीय चिंताएँ भी व्यक्त की गई हैं।
- गुजरात ने 12 अगस्त 2026 को गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की पुस्तकालयों को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए 'ग्रामीण ज्ञान सेतु' मोबाइल अनुप्रयोग शुरू किया। यह पहल केंद्र और शाखा मॉडल (Hub-and-Spoke Model) पर आधारित है, जिसमें गाँवों के पुस्तकालयों को चार केंद्रीय पुस्तकालयों से जोड़ा गया है। इन केंद्रीय पुस्तकालयों में लगभग 2.80 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं। अधिकारियों के अनुसार, तीन महीनों के भीतर 752 पुस्तकालयों को आपस में जोड़ा गया। प्रारंभिक नेटवर्क में गांधीनगर, कलोल और साणंद के 63 ग्रामीण पुस्तकालय शामिल हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के तहत वित्तपोषित चार चलित पुस्तकालय वाहन प्रत्येक पखवाड़े गाँवों का दौरा करेंगे। ये वाहन पुस्तकों का आदान-प्रदान करने के साथ-साथ पाठकों द्वारा माँगी गई पुस्तकें भी उपलब्ध कराएँगे। इस पहल का शुभारंभ राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के अवसर पर किया गया। यह दिवस एस. आर. रंगनाथन के सम्मान में मनाया जाता है।
- कर्नाटक सरकार ने गुटखा और पान मसाला सहित तंबाकू एवं निकोटीन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30(2)(a) के तहत लगाया गया है। यह धारा जनस्वास्थ्य के हित में ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। इस प्रतिबंध के अंतर्गत पैकेटबंद और खुले गुटखा तथा पान मसाला के साथ-साथ अलग से बेचे जाने वाले तंबाकू या निकोटीन उत्पाद, जिन्हें अन्य पदार्थों में मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है, भी शामिल हैं। राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किए हैं। साथ ही, नागरिकों को नियमों के उल्लंघन की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि को लेकर विभिन्न रिपोर्टों में अंतर है। कुछ रिपोर्टों में 10 अगस्त 2026, जबकि कुछ में 15 जून 2026 की तिथि बताई गई है।
- लद्दाख ने दुर्लभ हिमालयी पक्षी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उसके संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 11 से 14 अगस्त 2026 तक अपने पहले काली गर्दन वाले सारस महोत्सव का आयोजन किया। काली गर्दन वाला सारस को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (IUCN) द्वारा निकट संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। यह पक्षी मुख्य रूप से ऊँचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। भारत में लद्दाख इसका प्रमुख प्रजनन क्षेत्र है, विशेष रूप से त्सो कार, हानले और चांगथांग के आसपास के क्षेत्र इसके लिए महत्वपूर्ण हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इसमें संरक्षणवादी, शोधकर्ता और विशेषज्ञ शामिल हुए। इस आयोजन के माध्यम से स्थानीय आजीविका और पारिस्थितिकी पर्यटन को भी बढ़ावा दिया गया। काली गर्दन वाले सारस के सामने प्रमुख खतरों में आर्द्रभूमियों का क्षरण, जलवायु परिवर्तन, बुनियादी ढाँचे का विस्तार, प्रदूषण और पर्यटन से होने वाला व्यवधान शामिल हैं।



ALL EXAMS, **ONE** SUBSCRIPTION

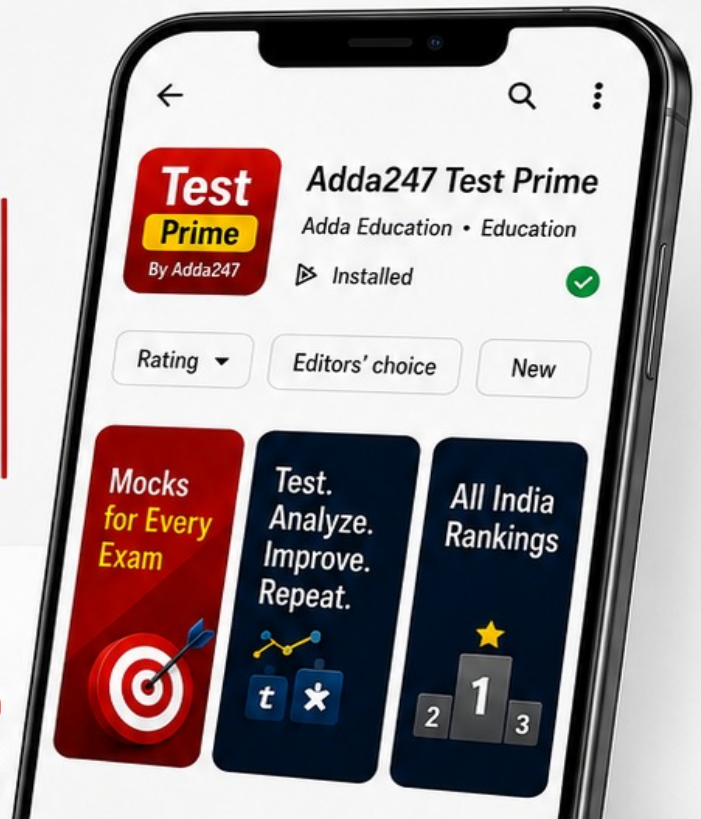


Test. Analyze. Improve. Repeat.



*Don't just
prepare.
Perform.*

Test Prime – built only
for mock tests.



1,50,000+
Mock Tests



25,000+
Previous Year
Papers



800+
Exam
Covered



500%
Refund on
Selection



5 lakh+
Free Quizzes



Daily
Free PDFs



Top Alerts
Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- ✓ Multilingual
- ✓ Detailed Solution
- ✓ Strong and Weak Areas
- ✓ All India Rankings



Safe & Reliable



Trusted by
Lakhs of Aspirants

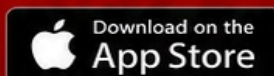


Your Success,
Our Mission



**DOWNLOAD
TEST PRIME**

Your Success Partner!



- कर्नाटक सरकार ने SAMASTA के चरणबद्ध क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। यह एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य मंच है, जिसे कागज आधारित स्वास्थ्य अभिलेखों के स्थान पर उपयोग करने के लिए विकसित किया गया है। यह मंच आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) से जुड़ा होगा और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम और स्वास्थ्य निरीक्षकों के माध्यम से संचालित किया जाएगा। SAMASTA में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से डेटा दर्ज करने की सुविधा है। इससे कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी इसका उपयोग आसान होगा। यह मंच आशा कार्यकर्ताओं की डायरी में दर्ज किए जाने वाले डेटा तत्वों की संख्या 485 से घटाकर 134 डिजिटल बिंदुओं तक कर देता है। इससे डेटा दर्ज करने से संबंधित कार्यभार में लगभग 75% की कमी आने की संभावना है। SAMASTA में परिवार पहचान संख्या, आधार सत्यापन और ABHA ID को एकीकृत किया गया है। उडुपी में किए गए पायलट प्रोजेक्ट में 95% लाभार्थियों का पंजीकरण और 85% स्वास्थ्य जाँच पूरी की गई। इसके साथ 4 लाख से अधिक ABHA ID को भी जोड़ा गया।
- कर्नाटक सरकार ने पात्र 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों के लिए 'संध्या किरण अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना' को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को फ्लोटर आधार पर प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा कवरेज प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा निर्धारित अस्पतालों में द्वितीयक, तृतीयक और आपातकालीन उपचार के लिए उपलब्ध होगी। यह योजना आयुष्मान भारत-आरोग्य कर्नाटक के अंतर्गत संचालित होगी और इसका क्रियान्वयन सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। सेवा पेंशनभोगी मूल पेंशन का 1.25%, जबकि पारिवारिक पेंशनभोगी मूल पेंशन का 0.75% योगदान करेंगे। योजना के तहत अनुमानित वार्षिक प्रीमियम संग्रह ₹117 करोड़ होगा, जबकि उपचार पर अनुमानित खर्च ₹81.75 करोड़ होगा। यदि योजना के कोष का उपयोग 85% से अधिक हो जाता है, तो योगदान की दर में 5 आधार अंकों की वृद्धि की जा सकती है।
- उत्तर प्रदेश के झाँसी में स्थित 140 वर्ष पुरानी परिछा वीयर को 13 अगस्त 2026 को अंतरराष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकास आयोग (ICID) द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता दी गई। बेतवा नदी पर निर्मित यह पत्थर की चिनाई वाली वीयर 1,174 मीटर लंबी और 16.8 मीटर ऊँची है। इसमें 318 स्टील के फॉलिंग शटर हैं तथा इसकी जलाशय क्षमता 2,400 मिलियन घन फीट है। इससे जुड़ी बेतवा नहर प्रणाली लगभग 2,654 किलोमीटर लंबी है और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में 4,28,360 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। इसका निर्माण 1881 में शुरू हुआ था और यह सिंचाई प्रणाली 1886 में चालू की गई थी। इस सम्मान का औपचारिक पुरस्कार अक्टूबर 2026 में फ्रांस में प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा ने स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह के दौरान इतिहास रच दिया, जब पलवल में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा ने दो गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाए। खेल एवं युवा सशक्तीकरण मंत्री गौरव गौतम के नेतृत्व में 13 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम में 5 किलोमीटर लंबा और

10 फुट चौड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। हजारों विद्यार्थियों, युवा समूहों, महिलाओं, युद्ध के पूर्व सैनिकों और स्थानीय निवासियों ने इसमें भाग लिया। जुलूस ने लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी तय की और पलवल के 20 प्रमुख स्थानों से होकर गुजरा। इसने ध्वज के साथ सबसे लंबा सामूहिक मार्च और राष्ट्रीय ध्वज थामे लोगों की सबसे अधिक संख्या के रिकॉर्ड स्थापित किए। इस कार्यक्रम ने स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान देशभक्ति, सामुदायिक भागीदारी और भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण को बढ़ावा दिया।

अंतर्राष्ट्रीय मामले

- ईरान ने पूर्व IRGC कमांडर मोहसेन रेज़ाई को सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (SNSC) का प्रमुख नियुक्त किया है, उन्होंने मोहम्मद बाघेर ज़ोलघदर का स्थान लिया है। यह नियुक्ति हार्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास बढ़ते तनाव के बीच हुई है, जो एक महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा मार्ग है, तथा ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ओमान से जुड़ी जारी अप्रत्यक्ष कूटनीति के बीच भी हुई है। रेज़ाई ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान के अनुभवी सदस्य हैं और पहले देश के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का समर्थन कर चुके हैं। SNSC प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और विदेश नीति से संबंधित मामलों का समन्वय करती है, जिसमें प्रमुख निर्णयों के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता की मंजूरी आवश्यक होती है। उनकी नियुक्ति से क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान की निर्णय लेने की संरचना में सुरक्षा-केंद्रित आवाज़ मजबूत हो सकती है।
- भारत ने 7 अगस्त 2026 को ज़िनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को पाँच युवा मोर उपहार में दिए, जिससे 1981 से चली आ रही एक परंपरा पुनर्जीवित हुई। इस झुंड में चार नीले भारतीय मोर और एक दुर्लभ सफेद नर मोर शामिल हैं, जो सभी Pavo cristatus प्रजाति के हैं, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इस समारोह में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची तथा संयुक्त राष्ट्र ज़िनेवा की महानिदेशक तातियाना वालोवाया शामिल हुईं। पक्षी प्रारंभ में एरियाना पार्क में तीन महीने के लिए एक अस्थायी पक्षीशाला में रहेंगे, जिसके बाद उन्हें 46 हेक्टेयर में फैले संयुक्त राष्ट्र ज़िनेवा परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। ज़िनेवा बायोपार्क ने उनके परिवहन और चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की। मूल परंपरा तब शुरू हुई थी जब इंदिरा गांधी ने 1981 में एक प्रजनन जोड़ा भेजा था।
- कोलंबिया ने एक शक्तिशाली 4 तीव्रता वाले भूकंप के पश्चिमी क्षेत्रों में आने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। इस भूकंप में 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई तथा कई लोग लापता या घायल हुए। इसका उपरिकेंद्र चोको में सैन होसे डेल पालमार के निकट था और इस भूकंप को 21^{वीं} सदी में कोलंबिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया गया। लगभग 107 किलोमीटर की इसकी मध्यम गहराई देश के जटिल विवर्तनिक पर्यावरण को दर्शाती है, जिसमें नाज़्का, दक्षिण अमेरिकी और कैरेबियाई प्लेटें शामिल हैं। कोलंबिया प्रशांत अग्नि वलय के भीतर स्थित है, जिसके कारण यह भूकंपीय गतिविधियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। कैली, बोगोटा और मेडेलिन जैसे प्रमुख शहर भी सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों के निकट होने के कारण भूकंप के जोखिम का सामना करते हैं।

- न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में आधिकारिक रूप से 15 अगस्त 2026 को मान्यता प्रदान की। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने इस तिथि को "भारत स्वतंत्रता दिवस" के रूप में घोषित किया, जबकि न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने "भारतीय स्वतंत्रता दिवस" की उद्घोषणा जारी की। इन घोषणाओं में भारतीय-अमेरिकी समुदायों के शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और नागरिक जीवन में योगदान को मान्यता दी गई है। ये घोषणाएँ बढ़ते भारत-अमेरिका सांस्कृतिक, आर्थिक और जन-से-जन संबंधों को भी रेखांकित करती हैं। हालाँकि, ये उद्घोषणाएँ राज्य-स्तरीय मान्यताएँ हैं और 15 अगस्त को अमेरिका का संघीय अवकाश नहीं बनाती हैं। मैसाचुसेट्स और बोस्टन इससे पहले इसी प्रकार की क्षेत्रीय मान्यताएँ जारी कर चुके हैं।
- लेबनान की संसद ने 11 अगस्त 2026 को मृत्युदंड समाप्त कर दिया और भविष्य में किए जाने वाले अपराधों के लिए मृत्युदंड के स्थान पर कठोर श्रम सहित आजीवन कारावास का प्रावधान किया। इस कानून के तहत वर्तमान में मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों की सजा भी कम कर दी गई है और फाँसी पर रोक की उस वास्तविक स्थिति को कानूनी रूप दिया गया है, जो 17 जनवरी 2004 से लागू थी। लेबनान कानूनी रूप से मृत्युदंड समाप्त करने वाला पहला मध्य पूर्वी देश बना और इसे जिवूती के बाद अरब राज्यों की लीग का दूसरा सदस्य बताया गया है। लगभग 84-85 मृत्युदंड प्राप्त कैदियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ ने इस निर्णय का स्वागत मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में किया।
- रूस ने घरेलू ईंधन आपूर्ति पर दबाव के कारण अगस्त 2026 में पहली बार भारत से पेट्रोल का आयात किया। पहला भारतीय माल गुजरात स्थित नायरा एनर्जी की वाडीनार रिफाइनरी से लादा गया और मिस्र के दमियेटा बंदरगाह के माध्यम से भेजा गया। रूसी तेल शोधन सुविधाओं पर बार-बार हुए हमलों ने घरेलू शोधन क्षमता को कम कर दिया है, जिसके कारण मॉस्को ने आपूर्ति की सुरक्षा के लिए पेट्रोल और डीजल के निर्यात को सीमित कर दिया। यह घटनाक्रम भारत-रूस ऊर्जा व्यापार में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाता है, जिसमें भारत एक प्रमुख वैश्विक तेल शोधन केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है और साथ ही रूसी कच्चे तेल की पर्याप्त मात्रा का आयात जारी रखता है।
- कई अमेरिकी राज्यों ने भारत की स्वतंत्रता, विरासत और भारतीय-अमेरिकी समुदायों के योगदान का उत्सव मनाते हुए 15 अगस्त 2026 को भारत दिवस या भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान्यता देने की घोषणाएँ जारी की हैं। डेलावेयर इस मान्यता को जारी करने वाला नवीनतम राज्य बना, जिसके बाद न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और मैसाचुसेट्स ने भी ऐसी घोषणाएँ कीं। डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेतृत्व, सेवा और राज्य की समृद्धि में योगदान को रेखांकित किया। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल और न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने भी घोषणाएँ जारी कीं। पूरे अमेरिका में भारतीय समुदाय ध्वजारोहण समारोहों, परेडों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सामुदायिक आयोजनों के माध्यम से 15 अगस्त मनाते हैं, जो मजबूत भारत-अमेरिका जन-से-जन संबंधों को दर्शाता है।
- रूस ने पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ को यूक्रेन के सरकारी स्वामित्व वाले ओश्राडबैंक द्वारा दायर निवेश संधि विवाद में

अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह मामला उन परिसंपत्तियों और परिचालनों से संबंधित है, जिन्हें बैंक के अनुसार 2022 में रूस के आक्रमण के बाद उसने डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसॉन और ज़ापोरिझिया में खो दिया था। इस विवाद की सुनवाई 1998 के रूस-यूक्रेन निवेश संरक्षण समझौते के तहत की जा रही है। तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण में यूनानी मध्यस्थ स्टावरोस ब्रेकौलाकिस और कोस्टा रिका की छाला जिमेनेज़ अध्यक्ष के रूप में शामिल हैं। चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए थे। बताया जाता है कि उन्होंने इससे पहले अन्य संधि विवादों में मॉस्को के अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था।

- तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षरित मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत राजनीतिक और सैन्य समन्वय तंत्र स्थापित करेंगे। समझौते में कहा गया है कि किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला सभी सदस्यों पर हमले के रूप में माना जाएगा, जिससे NATO के अनुच्छेद 5 के समान व्यापक रूप से सामूहिक रक्षा व्यवस्था स्थापित होगी। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सैन्य प्रमुख इन समन्वय तंत्रों में भाग लेंगे। तीनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास की भी योजना बना रहे हैं, जबकि सहयोग का विस्तार रक्षा उद्योग में संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी साझा करने तक हो सकता है। यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच अधिक सैन्य अंतःसंचालनीयता और रणनीतिक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है।
- ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का "हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य पर पूर्ण नियंत्रण" है और जोर देकर कहा कि यह रणनीतिक जलमार्ग अभी भी अवरुद्ध है। फारस की खाड़ी जलडमरूमध्य प्राधिकरण ने कहा कि इसे फिर से खोलना ईरान की शर्तों पर निर्भर करेगा। ट्रंप ने अमेरिकी नौसैनिक तैनाती को "इस्पात की दीवार" बताया और कहा कि वॉशिंगटन नियंत्रण बनाए रखेगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसेन रेज़ाई ने अमेरिका से युद्ध और नाकाबंदी समाप्त करने, जमी हुई ईरानी परिसंपत्तियों को जारी करने तथा लेबनान और गाजा को शामिल करने वाले क्षेत्रीय युद्धविराम को स्वीकार करने की मांग की। हॉर्मुज़ से लगभग वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का 20% गुजरता है, जिससे यह विवाद ऊर्जा बाजारों और समुद्री परिवहन की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

बैंकिंग/अर्थशास्त्र/व्यवसाय समाचार

- सरकार ने स्पष्ट किया कि UPI उपयोगकर्ता लेनदेन शुल्क देना जारी नहीं रखेंगे, तथा सभी व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) भुगतान निःशुल्क बने रहेंगे। यह स्पष्टीकरण भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS अधिनियम) में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर हुई चर्चा के बाद आया। भविष्य में कोई भी मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (MDR) केवल एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक के सीमित श्रेणी के व्यापारी लेनदेन पर और मामूली दर पर लागू होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी UPI भुगतान निःशुल्क बने रहेंगे। संसद द्वारा कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दिए जाने के बाद, NPCI के नेतृत्व वाली UPI और सेवा संचालन समिति यह निर्णय करेगी कि MDR लागू किया जाए या नहीं। UPI ने जुलाई 2026 में ₹29.9 लाख करोड़ मूल्य के 2,366 करोड़ लेनदेन संसाधित किए।

- संसद ने बैंकर बुक साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया, जिसने बैंकर बुक साक्ष्य अधिनियम, 1891 का स्थान लिया है और न्यायालयीन कार्यवाहियों में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग अभिलेखों को स्पष्ट कानूनी मान्यता प्रदान की है। राज्य सभा ने 10 अगस्त 2026 को ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दी, जिसके पहले लोक सभा इसे पारित कर चुकी थी। यह प्रौद्योगिकी-तटस्थ कानून भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, क्लाउड, बैकअप और आपदा-पुनर्प्राप्ति प्रणालियों में संग्रहीत अभिलेखों को शामिल करता है। अभिलेखों का प्रमाणीकरण हस्तलिखित, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से किया जा सकता है। यह बैंक अधिकारियों को अनावश्यक न्यायालयीन समन से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जब उनका बैंक सीधे तौर पर मामले में शामिल न हो। विधेयक में लगभग 16 धाराएँ हैं और इसका विस्तार अन्य विनियमित वित्तीय संस्थाओं तक किया जा सकता है।
- वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, भारत का सरकारी ऋण-GDP अनुपात वित्त वर्ष 2026 में 2% रहा, जो 56.1% के लक्ष्य से 210 आधार अंक अधिक था। सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के लिए कम 55.6% का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए और कमी आवश्यक होगी। सरकारी देयताएँ वित्त वर्ष 2021 में GDP के 61.5% से घटकर वित्त वर्ष 2026 में 58.2% हो गईं, जबकि राजकोषीय घाटा 9.2% से घटकर 4.4% हो गया। लक्ष्य से अधिक ऋण अनुपात आंशिक रूप से नए राष्ट्रीय लेखा शृंखला के तहत संशोधित नाममात्र GDP अनुमानों से जुड़ा था, जिसमें वित्त वर्ष 2023 को आधार वर्ष बनाया गया है। सरकार ने वैश्विक आर्थिक जोखिमों के लिए ₹1 लाख करोड़ का आर्थिक स्थिरीकरण कोष भी स्थापित किया है।
- RBI का 101वाँ व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण, जो जुलाई 2026 में आयोजित किया गया, ने भारत की वित्त वर्ष 2027 की वास्तविक GDP वृद्धि के पूर्वानुमान को 5% से बढ़ाकर 6.6% कर दिया और खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.9% से बढ़ाकर 5% कर दिया। वित्त वर्ष 2028 के लिए अर्थशास्त्रियों को 7% वृद्धि और 4.5% मुद्रास्फीति की उम्मीद है, जो संभावित संतुलित आर्थिक विस्तार का संकेत देती है। सर्वेक्षण में वस्तु निर्यात वृद्धि 7%, आयात वृद्धि 9.9% और चालू खाते का घाटा GDP के 1.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2027 के लिए RBI का अपना वृद्धि अनुमान थोड़ा अधिक 6.7% है। प्रमुख जोखिमों में खाद्य और ईंधन की कीमतें, मानसून की स्थिति, भू-राजनीतिक तनाव, अल नीनो और वैश्विक व्यापार संबंधी अनिश्चितता शामिल हैं।
- बेंगलुरु स्थित सरला एविएशन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से डिजाइन संगठन अनुमोदन (DOA) प्राप्त हुआ है, जो भारत में उभरते विद्युत हवाई-टैक्सी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अनुमोदन नगरीय आवागमन के लिए विद्युत ऊर्ध्वाधर उड़ान और अवतरण (eVTOL) विमानों के विकास में सहायता करता है। सरला 2026 में भारत की तीसरी eVTOL DOA धारक बनी। इसके नियोजित विमान में छह यात्री और एक पायलट सवार हो सकते हैं और इसमें सात विद्युत मोटरों का उपयोग किया जाता है। कंपनी ने जुलाई 2026 में अपने आधे आकार के सिल्ला प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का उड़ान परीक्षण पूरा किया। भारत का लक्ष्य प्रमाणन, परीक्षण और अवसंरचना विकास के अधीन, 2028 तक बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में परिचालन विद्युत हवाई टैक्सियाँ शुरू करना है।
- एन. चंद्रशेखरन ने घोषणा की है कि वे फरवरी 2027 में अपना वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद टाटा संस के अध्यक्ष पद से हट जाएंगे और पुनर्नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे। उनका निर्णय पाँच वर्ष के प्रस्तावित विस्तार के बाद आया, जिसे कथित तौर पर टाटा संस के बोर्ड का सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त नहीं था। चंद्रशेखरन ने कंपनी की वार्षिक आम बैठक से पहले बोर्ड से उत्तराधिकार योजना शुरू करने को कहा है। यह घटनाक्रम टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच शासन और रणनीतिक मुद्दों को लेकर कथित मतभेदों के बीच हुआ है। घोषणा के बाद TCS, टाटा पावर और टाटा स्टील सहित प्रमुख टाटा समूह कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।
- MoSPI के नए CPI श्रृंखला के आधार पर जारी आँकड़ों के अनुसार, जिसमें 2024 को आधार वर्ष बनाया गया है, भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून में 4.38% की तुलना में जुलाई 2026 में 45% तक मामूली रूप से बढ़ गई। खाद्य कीमतें इसका प्रमुख कारण रहीं, जिसमें उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति बढ़कर 5.52% हो गई। ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति 5.79% रही, जबकि नगरीय खाद्य मुद्रास्फीति 5.05% रही। ग्रामीण खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.84% हो गई, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह 3.96% रही। अदरक, लहसुन और प्याज की कीमतों में तेज वृद्धि दर्ज की गई, जबकि आलू की कीमतों में गिरावट आई। प्रमुख राज्यों में तेलंगाना में मुद्रास्फीति सबसे अधिक 6.32% रही।
- Google ने तीन नई समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली केबल प्रणालियों की घोषणा की है, जो अमेरिका में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए पनामा, चिली, डोमिनिकन गणराज्य, बरमूडा और फ्लोरिडा को जोड़ेंगी। एलिसियोस केबल चिली, पनामा और डोमिनिकन गणराज्य को जोड़ेगी, जबकि कैनोआ डोमिनिकन गणराज्य को बरमूडा से और ओलालूज़ डोमिनिकन गणराज्य को फ्लोरिडा से जोड़ेगी। ये परियोजनाएँ चिली की क्षेत्रीय डिजिटल केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा का समर्थन करती हैं, जिसे फाइबर-ऑप्टिक अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन प्राप्त है। Google चिली और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाली हम्बोल्ट केबल का भी समर्थन कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि ये परियोजनाएँ व्यवसायों, आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय डिजिटल एकीकरण को बढ़ावा दे सकती हैं।
- विजय सिंह, टाटा ट्रस्ट्स के उपाध्यक्ष, ने सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) के न्यासी पद से इस्तीफा दे दिया है और 14 अगस्त 2026 को उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नवीनीकरण की मांग नहीं करेंगे। वे सर दाराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के न्यासी के रूप में कार्य करते रहेंगे। उनका जाना SRTT के न्यासियों के बीच कथित मतभेदों के बीच हुआ है। महाराष्ट्र राज्य चैरिटी आयुक्त ने कथित बोर्ड संरचना संबंधी उल्लंघनों की जाँच लंबित रहने तक SRTT को बोर्ड बैठकें आयोजित करने से रोक दिया है। SRTT ने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की है, जिसमें टाटा संस की वार्षिक आम बैठक पर संभावित प्रभावों का हवाला दिया गया है। सिंह और वेणु श्रीनिवासन टाटा संस की सूचीबद्धता का समर्थन करते हैं।

पुस्तक और लेखक समाचार

- पीएम मोदी ने राम नाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन किया: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की आत्मकथा, भारतीय गणराज्य की विजय: मेरा जीवन, मेरे संघर्ष, का विमोचन किया। मोदी ने इस पुस्तक को भारतीय लोकतंत्र, जनसेवा और दृढ़ता का एक महत्वपूर्ण विवरण बताया। उन्होंने कोविंद के कठिन बचपन को रेखांकित किया, जिसमें घर में लगी आग में उनकी माँ की मृत्यु भी शामिल थी, और परिवार के पालन-पोषण में उनके पिता के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सीमित संसाधनों से लेकर भारत के राष्ट्रपति पद तक कोविंद की यात्रा और एक राष्ट्र, एक चुनाव पहल में उनकी निरंतर भागीदारी पर भी चर्चा की तथा युवाओं को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

नियुक्तियाँ/इस्तीफे

- सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाकर 13 अगस्त 2027 तक कर दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 13 अगस्त 2026 से कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दी। राहुल नवीन 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल पहले 13 अगस्त 2026 को पूरा होने वाला था। उनका विस्तारित कार्यकाल उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति तिथि 31 जुलाई 2027 के बाद तक जारी रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख के रूप में वे धन शोधन, विदेशी मुद्रा उल्लंघनों और भगोड़े आर्थिक अपराधों से संबंधित जाँच की देखरेख करते हैं, जो PMLA, FEMA और FEOA सहित कानूनों के अंतर्गत आती हैं। यह निर्णय भारत की विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी के नेतृत्व में निरंतरता प्रदान करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 6 अगस्त 2026 के अपने प्रस्ताव में क्रमशः न्यायमूर्ति रविंद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को कलकत्ता और बॉम्बे उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की। न्यायमूर्ति घुगे वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनके पास लगभग 13 वर्षों का न्यायिक अनुभव है और उन्हें जून 2013 में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। न्यायमूर्ति त्रिपाठी, 2013 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाए गए वरिष्ठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जिन्हें बॉम्बे उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिफारिश की गई है। उन्हें दीवानी कानून का व्यापक अनुभव है और उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश के अपर स्थायी अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। दोनों सिफारिशों के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी और औपचारिक अधिसूचना आवश्यक है।
- डॉ. श्रीनिवास कुमार तुम्मला, एक प्रतिष्ठित समुद्र विज्ञानी और विशिष्ट वैज्ञानिक, ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। उन्हें दूरसंवेदी, उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय जोखिमों और आपदा प्रबंधन में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी के बाद उन्होंने INCOIS में भारत की उन्नत सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्य किया। INCOIS के निदेशक के रूप में उन्होंने

मछली पकड़ने संबंधी परामर्श, प्रवाल भित्ति चेतावनियों और बहु-जोखिम भेद्यता मानचित्रण सहित समुद्री सेवाओं का विस्तार किया। उन्होंने UNESCO-IOC के अंतर्गत हिंद महासागर सुनामी चेतावनी और शमन प्रणाली सचिवालय का भी नेतृत्व किया। उनके पुरस्कारों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2010 और भारतीय राष्ट्रीय भू-स्थानिक पुरस्कार 2008 शामिल हैं।

- दीप्ति गौर मुखर्जी, 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की IAS अधिकारी, को 10 अगस्त 2026 को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा किए गए वरिष्ठ नौकरशाही फेरबदल का हिस्सा थी। उन्होंने विनीत जोशी का स्थान लिया, जिन्हें पंचायती राज मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया। मुखर्जी ने इससे पहले अगस्त 2024 से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया था। उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षा और केंद्रीय उच्च शिक्षा नीति का प्रबंधन करता है। अन्य नियुक्तियों में पल्लवी जैन गोविल को कॉर्पोरेट कार्य सचिव और सुनील पालिवाल को युवा कार्य सचिव नियुक्त किया गया।

रक्षा समाचार

- भारत-अमेरिका नौसेना विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण (EOD) अभ्यास 2026 की शुरुआत 10 अगस्त को दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में हुई और यह 14 अगस्त तक चला। पाँच दिवसीय द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य विशेषज्ञ गोताखोरी और EOD टीमों के बीच अंतःसंचालनीयता, परिचालन समन्वय और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना था। गतिविधियों में विषय विशेषज्ञों के आदान-प्रदान, पारस्परिक प्रशिक्षण, उपकरण प्रदर्शन और अनुकरण किए गए परिचालन परिदृश्यों पर आधारित व्यावहारिक अभ्यास शामिल थे। EOD विशेषज्ञों को विस्फोटक खतरों की पहचान करने, उन्हें संभालने और निष्क्रिय करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनकी क्षमताएँ समुद्री सुरक्षा, नौसैनिक अभियानों और पानी के नीचे स्थित अवसंरचना की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इस अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं को तकनीकी विशेषज्ञता और परिचालन कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान करने का अवसर दिया, जिससे भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग और मजबूत हुआ।
- अभ्यास टैलिस्मैन सेबर 2027 का आयोजन 9 से 22 अगस्त 2027 तक किया जाएगा, जिससे यह 14 दिवसीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होगा, जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका करेंगे। आगामी संस्करण में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और 24 अन्य साझेदार देशों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत की भागीदारी बढ़ने की संभावना है, जो मजबूत होते भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों और बढ़ती हिंद-प्रशांत भागीदारी को दर्शाता है। 1 जून 2026 को आयोजित भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता के दौरान इस निर्णय का स्वागत किया गया, जिसकी सह-अध्यक्षता राजनाथ सिंह और रिचर्ड मार्ल्स ने की। लगभग 800 कर्मी इसकी योजना बनाने में शामिल हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतःसंचालनीयता, संयुक्त परिचालन क्षमताओं, बहुराष्ट्रीय योजना और तत्परता में सुधार करना है।

- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने महाराष्ट्र स्थित अपनी नासिक सुविधा में Su-30MKI लड़ाकू विमानों का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है, जिससे भारत के घरेलू रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिली है। पुनः शुरू की गई उत्पादन लाइन भारतीय वायु सेना के लिए 12 नए Su-30MKI लड़ाकू विमानों का निर्माण करेगी। इसके लिए दिसंबर 2024 में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसका उद्देश्य दुर्घटनाओं में नष्ट हुए विमानों को बदलना है। पहला विमान 2027-28 में मिलने की उम्मीद है और आपूर्ति 2029 तक पूरी हो जाएगी। HAL की नासिक सुविधा ने पहले रूस से लाइसेंस के तहत 222 Su-30MKI विमानों का उत्पादन किया था। नए विमानों में लगभग 50%-62.6% स्वदेशी सामग्री होने की उम्मीद है। भारत अलग से ₹60,000 करोड़ के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है, जिसमें एवियोनिक्स, स्वदेशी रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ शामिल हैं।
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने 11 अगस्त 2026 को कोलकाता में भारतीय नौसेना के दूसरे अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत (NGOPV) श्रुति का जलावतरण किया। यार्ड 3037 के रूप में नामित इस पोत का जलावतरण पहले NGOPV संगमित्रा के 20 मई को जलावतरण के तीन महीने से भी कम समय बाद हुआ। GRSE एक 11-पोत कार्यक्रम के तहत चार NGOPVs का निर्माण कर रहा है और शेष पोतों का जलावतरण वित्तीय वर्ष के अंत तक होने की उम्मीद है। यह परियोजना भारत की समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा और स्वदेशी नौसैनिक पोत निर्माण क्षमताओं को मजबूत करती है तथा नौसेना की बढ़ती परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करती है।
- भारतीय वायु सेना (IAF) और रॉयल मलेशियाई वायु सेना ने 10 अगस्त को मलेशिया के सुबांग वायुसेना अड्डे पर उदारा शक्ति 2026 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया। पाँच दिवसीय अभ्यास में 83 कर्मियों ने भाग लिया और इसका ध्यान जटिल वायु-युद्धाभ्यास, हवा-से-हवा ईंधन भरने और रणनीतिक वायु परिवहन अभियानों पर रहा। भारत ने नंबर 101 स्क्वाड्रन के चार राफेल लड़ाकू विमान और दो C-17 ग्लोबमास्टर III विमान तैनात किए, जबकि मलेशिया ने दो Su-30MKI लड़ाकू विमान, दो F/A-18D लड़ाकू विमान और एक A400M परिवहन विमान तैनात किया। दोनों वायु सेनाओं के बीच अंतःसंचालनीयता, परिचालन समन्वय और पारस्परिक समझ को मजबूत करने के लिए संयुक्त क्षेत्रीय प्रशिक्षण और विषय विशेषज्ञों का आदान-प्रदान भी किया गया।
- NABARD ने 10 अगस्त 2026 को राष्ट्रीय जलवायु स्टैक नवाचार चुनौती के विजेताओं की घोषणा की। इसका आयोजन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और डालबर्ग एडवाइजर्स के साथ जलवायु-लचीली कृषि में डेटा (DiCRA) के अंतर्गत किया गया। सैटशयोर एनालिटिक्स इंडिया ने मौसम संबंधी जोखिम के आधार पर गाँवों की रैंकिंग करने वाले जलवायु भेद्यता सूचकांक के लिए ₹15 लाख का प्रथम पुरस्कार जीता। EXPERIQS को सूखा निगरानी और फसल-चक्र पूर्वानुमान के लिए ₹10 लाख का द्वितीय पुरस्कार मिला, जबकि VARSAPRADAYA ने जोखिम आकलन और सिंचाई योजना के लिए ₹5 लाख का तृतीय पुरस्कार जीता। 150 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनसे 20 प्रोटोटाइप और 11 अंतिम प्रतिभागी चुने गए। यह पहल जलवायु-लचीली कृषि और ग्रामीण ऋण-जोखिम आकलन को बढ़ावा देती है।
- भारत ने बुखारेस्ट, रोमानिया में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषाविज्ञान ओलंपियाड 2026 में चार पदक जीते, जिनमें एक स्वर्ण और तीन कांस्य पदक शामिल हैं। श्रीलक्ष्मी वेंकटरमन ने 70.0 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि आरव अनिल राव, निशांत शंकर लक्ष्मणन और अद्वय मिश्रा ने कांस्य पदक हासिल किए। सोहम अमित पेडनेकर को सम्माननीय उल्लेख प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में 40 से अधिक देशों के 255 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इसमें तर्क, व्याकरण, भाषा विश्लेषण और प्रतिरूप पहचान की परीक्षा ली गई। 2009 में पहली बार भाग लेने के बाद भारत के व्यक्तिगत पदकों की संख्या अब 37 पदक हो गई है, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 22 कांस्य शामिल हैं। पाणिनि भाषाविज्ञान ओलंपियाड भारतीय प्रतिभागियों का चयन करता है।
- भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी दीपक धर को सांख्यिकीय यांत्रिकी और जटिल तंत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अब्दुस सलाम अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र (ICTP) द्वारा प्रतिष्ठित 2026 डिराक पदक से सम्मानित किया गया। 8 अगस्त 2026 को इटली के ट्रिएस्टे में घोषित यह सम्मान बर्नार्ड डेरिडा, मार्क मेज़ार्ड और हाइम सोमपोलिंस्की के साथ साझा किया गया है। धर सैंडपाइल मॉडल और स्व-संगठित क्रांतिकता पर अपने शोध के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनके व्यापक अनुप्रयोग अनुकूलन, सैद्धांतिक तंत्रिका विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं। 1985 में ICTP द्वारा स्थापित डिराक पदक प्रतिवर्ष 8 अगस्त को भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक की जयंती के अवसर पर प्रदान किया जाता है और इसके साथ 5,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया जाता है।
- भारत ने बुखारेस्ट, रोमानिया में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय भाषाविज्ञान ओलंपियाड 2026 में चार पदक जीते, जिनमें एक स्वर्ण और तीन कांस्य पदक शामिल हैं। श्रीलक्ष्मी वेंकटरमन ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, जबकि आरव अनिल राव, निशांत शंकर लक्ष्मणन और अद्वय मिश्रा ने कांस्य पदक हासिल किए। सोहम अमित पेडनेकर को सम्माननीय उल्लेख प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता में रटे हुए ज्ञान के बजाय तार्किक तर्क, व्याकरण, भाषा विश्लेषण और प्रतिरूप पहचान की परीक्षा ली जाती है। भारत, जिसने 2009 में पहली बार भाग लिया था, अब 37 पदक जीत चुका है, जिनमें छह स्वर्ण, नौ रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। टीम का चयन पाणिनि भाषाविज्ञान ओलंपियाड के माध्यम से किया गया और IIIT हैदराबाद में प्रशिक्षण दिया गया।

पुरस्कार और मान्यताएँ

- भारतीय सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी दीपक धर को 8 अगस्त 2026 को इटली के ट्रिएस्टे में अब्दुस सलाम अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र (ICTP) द्वारा 2026 डिराक पदक का प्राप्तकर्ता घोषित किया गया। वे यह सम्मान बर्नार्ड डेरिडा, मार्क मेज़ार्ड और हाइम सोमपोलिंस्की के साथ साझा करते हैं। यह पुरस्कार साम्यावस्था और असाम्यावस्था सांख्यिकीय यांत्रिकी, अनुकूलन, सैद्धांतिक तंत्रिका विज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उनके योगदान को मान्यता देता है। धर विशेष रूप से सैंडपाइल मॉडल और स्व-संगठित क्रांतिकता पर अपने शोध के लिए जाने जाते हैं, जो यह समझाता है कि जटिल तंत्र स्वाभाविक रूप से क्रांतिक अवस्थाओं तक कैसे पहुँचते हैं। 1985 में ICTP द्वारा स्थापित डिराक पदक प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इसके साथ 5,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया जाता है।

- स्वतंत्रता दिवस 2026 सम्मान के तहत पुलिस और अग्निशमन सेवा के कर्मियों को कुल 301 वीरता पदक प्रदान किए गए, जिनमें 272 पुलिस कर्मी और 29 अग्निशमन सेवा कर्मी शामिल हैं। इन पुरस्कारों से जीवन और संपत्ति को बचाने, अपराध रोकने और अपराधियों को पकड़ने में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। 197 पुरस्कार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के कर्मियों को, 51 जम्मू-कश्मीर के कर्मियों को, 12 पूर्वोत्तर के कर्मियों को और 41 अन्य क्षेत्रों के कर्मियों को दिए गए। कुल मिलाकर पुलिस, अग्निशमन सेवाओं, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधारात्मक सेवाओं के 1,057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, 92 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 664 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए गए।
- गज गौरव पुरस्कार 2026 विश्व हाथी दिवस समारोह के दौरान 13 अगस्त को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्रदान किए गए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान के सात महावतों को हाथियों और गैंडों से संबंधित बाढ़ बचाव प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। मंत्रालय ने "30 जाइंट स्टेप्स" जारी किया, जिसमें 2020 से 2026 के बीच परियोजना हाथी की 30 उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मानव-हाथी संघर्ष के लिए ₹500 करोड़ की सरकारी सहायता से एक क्षेत्रीय कार्ययोजना शुरू की गई। आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने H.A.N.U.M.A.N. वन्यजीव निगरानी पहल भी शुरू की।

रैंकिंग एवं रिपोर्ट्स समाचार

- 2026 हुरुन इंडिया पारिवारिक व्यवसाय रैंकिंग विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख भारतीय कारोबारी परिवारों की मजबूती को दर्शाती है। अंबानी परिवार ₹25,82,800 करोड़ के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मूल्यांकन के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, इसके बाद बिड़ला परिवार ₹8,13,700 करोड़ और जिंदल परिवार ₹8,01,800 करोड़ के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। बजाज परिवार ₹7,70,400 करोड़ के साथ चौथे, जबकि महिंद्रा परिवार ₹5,14,600 करोड़ के साथ पाँचवें स्थान पर रहा। वेदांता से जुड़े अनिल अग्रवाल परिवार ₹4,45,500 करोड़ के साथ छठे स्थान पर रहा। मुरुगप्पा, नाडार, प्रेमजी और दानी-चोक्सी-वकील परिवारों ने शीर्ष 10 में स्थान बनाया। ये परिवार ऊर्जा, धातु, प्रौद्योगिकी, वित्त और ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

खेल समाचार

- अश्विमा चालिहा ने 9 अगस्त को दक्षिण कोरिया के असान में कोरिया मास्टर्स 2026 का खिताब जीता और चीन की चौथी वरीयता प्राप्त हान कियान शी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराया। शुरुआती गेम हारने के बाद भारतीय बाएँ हाथ की खिलाड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए मुकाबले को बराबरी पर ला दिया और निर्णायक गेम में दबदबा बनाया। इस जीत से उन्हें पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब मिला और यह उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। विश्व नंबर 50 की 26 वर्षीय खिलाड़ी को रैंकिंग में भी बड़ा लाभ मिला। उनकी यह जीत दो वर्ष पहले कोरिया ओपन के बाद गंभीर घुटने की चोट, सर्जरी

और पुनर्वास के बाद शानदार वापसी को दर्शाती है तथा उनके दृढ़ संकल्प और प्रतिस्पर्धात्मक वापसी को उजागर करती है।

- भारतीय ऊँची कूद खिलाड़ी बसंत कुमार मेघवाल ने विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और 2.21 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। राजस्थान के अनूपगढ़ के 19 वर्षीय एथलीट ने प्रतियोगिता के चौथे दिन यह ऊँचाई पार की। अल्जीरिया के यूनुस अयाची ने स्वर्ण और ब्रिटेन के ओटिस पूल ने कांस्य पदक जीता, जबकि तीनों खिलाड़ियों ने 2.21 मीटर की ऊँचाई पार की। अंतिम स्थानों का निर्धारण काउंटबैक नियम के आधार पर किया गया, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी 2.24 मीटर पार नहीं कर सका। अयाची ने 2.21 मीटर अपनी पहली कोशिश में, मेघवाल ने दूसरी और पूल ने तीसरी कोशिश में पार किया। मेघवाल के रजत पदक के साथ भारत की पदक संख्या दो हो गई, इससे पहले आशीष यादव ने भाला फेंक में रजत पदक जीता था।
- भारत ने U-23 राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के शुरुआती दिन नाइजीरिया के लागोस में 17 पदक जीते, जिसमें 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। ये पदक फाइनल, एपी और सेबर स्पर्धाओं में जीते गए। निखिल वाघ ने पुरुष सेबर में स्वर्ण पदक जीता, जबकि जॉयस अशिता, प्राची लोहान और जेफरलिन ने क्रमशः महिला फाइनल, महिला एपी और महिला सेबर में स्वर्ण पदक हासिल किए। कई अन्य भारतीय तलवारबाजों ने रजत और कांस्य पदक भी जीते। चैंपियनशिप 9 अगस्त को शुरू हुई और 14 अगस्त 2026 तक चली। U-23 प्रतियोगिता में 23 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी भाग लेते हैं और इसमें तलवारबाजी की तीनों ओलंपिक स्पर्धाएँ फाइनल, एपी और सेबर शामिल हैं।
- युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 12 अगस्त 2026 को शासन संबंधी कमियों का हवाला देते हुए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया (TTFI) की मान्यता निलंबित कर दी। फेडरेशन कथित रूप से निर्धारित अवधि के भीतर संगठनात्मक चुनाव कराने में विफल रहा और कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिया। मंत्रालय ने भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को अस्थायी रूप से टेबल टेनिस प्रशासन संभालने के लिए एक तदर्थ समिति गठित करने का निर्देश दिया। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक नियमों के अनुरूप फेडरेशन की संरचना बहाल नहीं हो जाती, जिसमें अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (ITTF) के साथ समन्वय भी शामिल होगा। यह कार्रवाई भारतीय खेल निकायों में पारदर्शी चुनाव, पारदर्शिता संबंधी आवश्यकताओं और उचित शासन के महत्व को रेखांकित करती है।
- जम्मू और कश्मीर 1 से 5 अक्टूबर तक श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में ईरानी कप 2026 की मेजबानी करेगा। पाँच दिवसीय प्रथम श्रेणी मुकाबले में जम्मू और कश्मीर का सामना रेस्ट ऑफ इंडिया से होगा, जिसके बाद टीम ने 2025-26 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। जम्मू और कश्मीर ने फाइनल में पहली पारी की बढ़त के आधार पर कर्नाटक को हराया था। स्टेडियम में मीडिया, कमेंट्री, लाइव प्रसारण और दर्शकों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता होगी। पारस डोगरा के जम्मू और कश्मीर की कप्तानी करने की उम्मीद है, जबकि स्विंग गेंदबाज औकिब नबी डार 60 रणजी विकेट लेने के बाद इस मुकाबले में उतरेगा। बीसीसीआई ने छह साल के निलंबन के बाद जुलाई 2024 में जेकेसीए के मेजबानी अधिकार बहाल किए थे।

- भारतीय पैरा-साइकिलिस्टों ने 7-10 अगस्त 2026 तक ओडेंस में आयोजित यूसीआई पैरा-स्पोर्ट डेनमार्क ग्रां प्री में 12 पदक जीते। भारत ने ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में दो स्वर्ण, पाँच रजत और पाँच कांस्य पदक हासिल किए। आंध्र प्रदेश के अरशद शेख ने एमसी2 वर्ग में दो स्वर्ण सहित छह पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। गुजरात के 17 वर्षीय विश्व वसानी ने डब्ल्यूसी3 वर्ग में विभिन्न स्पर्धाओं में चार कांस्य पदक जीते। महाराष्ट्र के 16 वर्षीय अंशुमान धूमल ने दो रजत पदक जोड़े। इस शानदार प्रदर्शन ने पैरा-साइकिलिंग में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया और भविष्य की प्रमुख पैरा-खेल प्रतियोगिताओं से पहले मूल्यवान अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्रदान किया।

योजनाओं से संबंधित समाचार

- दिल्ली लक्ष्मी योजना ने शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर पाँच लाख पंजीकरण का आँकड़ा पार कर लिया, जो राजधानी की महिलाओं के बीच मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। इस उपलब्धि से पहले पोर्टल पर 4.87 लाख पंजीकरण और 1.99 लाख जमा किए गए आवेदन दर्ज किए गए थे। शुरुआत में महिला समृद्धि योजना के रूप में स्वीकृत इस योजना का नाम बदलकर महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। पात्र लाभार्थियों को दो बचत विकल्पों के माध्यम से ₹2,500 मासिक प्राप्त होते हैं। एक विकल्प में CBDC वॉलेट के माध्यम से ₹1,000 और RD/FD के माध्यम से ₹1,500, जबकि दूसरे विकल्प में पूरी ₹2,500 राशि RD/FD के माध्यम से बचाई जाती है। यह योजना तत्काल वित्तीय सहायता के साथ दीर्घकालिक बचत और आर्थिक सुरक्षा को जोड़ती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित समाचार

- भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने तिरुवनंतपुरम स्थित HEX20 के साथ तीन समर्पित मिशनों के लिए एक बहु-प्रक्षेपण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पृथ्वी-अवलोकन और पेलोड प्रदर्शन शामिल हैं। प्रक्षेपण 2027 की चौथी तिमाही से शुरू होने हैं और इनमें स्काईरूट के विक्रम-श्रृंखला के रॉकेटों का उपयोग किया जाएगा। यह समझौता 18 जुलाई 2026 को श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 की सफल पहली कक्षीय उड़ान के बाद हुआ, जिसने इसे निम्न पृथ्वी कक्षा में ग्राहक पेलोड तैनात करने वाला भारत का पहला निजी रूप से विकसित कक्षीय-श्रेणी का प्रक्षेपण यान बनाया। स्काईरूट की योजना 2026 के अंत में एक और विक्रम-1 परीक्षण मिशन करने और दीर्घकाल में प्रति वर्ष 12 प्रक्षेपणों की उत्पादन क्षमता हासिल करने की है, जिससे भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
- नासा ने भारत-अमेरिका सहयोग का विस्तार करते हुए आर्टेमिस समझौते के तहत इसरो को अपने चंद्रमा आधार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस आमंत्रण पर 5-6 अगस्त 2026 को बेंगलुरु में आयोजित भारत-अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की नौवीं बैठक के दौरान चर्चा हुई। चर्चाओं में चंद्रमा पर सहयोग, वैज्ञानिक डेटा साझा करना और यूएस-इंडिया ट्रस्ट पहल शामिल थे। भारत ने जून 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो शांतिपूर्ण और जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण का समर्थन करता है। यह सहयोग सफल निसार मिशन पर आधारित है और इसमें आर्टेमिस संरचना से जुड़ी भविष्य की चंद्र गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं, जिनमें ओरियन अंतरिक्ष यान, गेटवे चंद्र स्टेशन और मानव चंद्र मिशन शामिल हैं।

- IIT आईआईटी गुवाहाटी ने CO₂ अवशोषण, बायोमास उत्पादन और जैव-ऊर्जा उत्पादन के लिए दो-चरणीय सूक्ष्म शैवाल संवर्धन प्रक्रिया विकसित की है। प्रोफेसर कौस्तुभ मोहंती और शोधार्थी दीपेश सिंह चौहान के नेतृत्व में किए गए इस शोध को नवीकरणीय ऊर्जा में प्रकाशित किया गया। पहले चरण में सूक्ष्म शैवाल की तीव्र वृद्धि के लिए 15% CO₂ का उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरे चरण में CO₂ की मात्रा घटाकर 5% कर दी जाती है तथा कैल्शियम और फॉस्फोरस मिलाए जाते हैं। प्रयोगों में 25.7% अधिक बायोमास, 35.4% अधिक CO₂ स्थिरीकरण, 1.86 गुना अधिक लिपिड उत्पादकता और 37.65% बेहतर अंतःकोशिकीय जैव-ऊर्जा दक्षता प्राप्त हुई। कैल्शियम-सहायित स्व-फ्लोक्युलेशन से 98.46% बायोमास संग्रहण पुनर्प्राप्ति दर हासिल हुई, जिससे ऊर्जा-गहन बायोमास पुनर्प्राप्ति की आवश्यकता कम हो सकती है।
- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने शोधकर्ताओं को एक संभावित “ब्लैक होल तारा”, जिसे MoM-BH-1* नाम दिया गया है, की पहचान करने में मदद की है। यह बिग बैंग के लगभग 660 मिलियन वर्ष बाद सिटस तारामंडल में अस्तित्व में था। शोधकर्ताओं के अनुसार, यह एक संभावित ऐसी वस्तु है जिसके केंद्र में एक ब्लैक होल है और उसके चारों ओर अत्यंत गर्म तथा घनी गैस मौजूद है। इसकी चमक सामान्य तारों की तरह नाभिकीय संलयन के बजाय ब्लैक होल की ओर गिरती गैस के कारण हो सकती है। यह वस्तु लगभग सौरमंडल के आकार की और असाधारण रूप से चमकीली बताई गई है। इसका अध्ययन अतिविशाल ब्लैक होल के तीव्र विकास को समझने और प्रारंभिक ब्लैक होल बीजों के बारे में सुराग प्राप्त करने में सहायता कर सकता है।
- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु ने 13 अगस्त 2026 को स्रवाणी जारी किया, जो स्पायर लैब द्वारा आर्टपार्क और गूगल के सहयोग से विकसित एक ओपन-सोर्स बहुभाषी वाक्-पहचान मॉडल है। यह 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में वाणी को पाठ में परिवर्तित करता है, जिसमें 20 अनुसूचित और 45 क्षेत्रीय भाषाएँ शामिल हैं। यह मॉडल 10 लिपियों और स्वचालित भाषा पहचान का समर्थन करता है। MIT लाइसेंस के तहत हरिंग फेस पर उपलब्ध होने के कारण इसका निःशुल्क उपयोग और संशोधन किया जा सकता है। स्रवाणी को प्रोजेक्ट वाणी के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, जिसके लिए 28 राज्यों के 165 जिलों में 1,56,000 लोगों से एकत्र किए गए 31,000 घंटे से अधिक के वार्तालाप संबंधी वाक् डेटा का उपयोग किया गया। गारो भाषा के लिए इसने 9.5% शब्द त्रुटि दर हासिल की।
- केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में संशोधित इंडिया कोड पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्नत प्लेटफॉर्म में कानूनों को समझना और खोजने को आसान बनाने के लिए एआई-सहायित संवाद, अर्थपूर्ण खोज, वाणी-आधारित खोज और बहुभाषी पहुँच जैसी सुविधाएँ शामिल की गई हैं। उपयोगकर्ता संशोधनों, विधायी इतिहास तथा अधिनियमों और अधीनस्थ कानूनों के बीच संबंधों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही इसे ई-गजट प्रणाली से जोड़ा गया है। पोर्टल में बेहतर दस्तावेज देखने की सुविधा, क्यूआर-कोड आधारित पहुँच और नागरिक प्रतिक्रिया की सुविधा भी उपलब्ध है। इसकी प्रमुख विशेषता आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में कानूनों तक एआई-सहायित पहुँच है। इंडिया कोड केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के कानूनों के लिए एक एकीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है।

- इसरो निम्न पृथ्वी कक्षा में संचालित उपग्रह समूहों से उत्पन्न होने वाले अंतरिक्ष मलबे को कम करने के प्रयासों को मजबूत कर रहा है। इसकी रणनीति में मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन (DFSM), सक्रिय मलबा हटाना (ADR), मिशन के बाद निपटान और कक्षीय क्षय मानदंड शामिल हैं। अंतरिक्ष मलबे में निष्क्रिय उपग्रह, प्रयुक्त रॉकेट चरण और टकराव से उत्पन्न टुकड़े शामिल होते हैं, जो सक्रिय अंतरिक्ष यानों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसरो ने ADR के लिए कक्षा में प्रारंभिक प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, हालांकि पूर्ण मलबा-हटाने वाली प्रणाली के परिचालन प्रक्षेपण की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है। भारतीय अंतरिक्ष मिशन भारतीय अंतरिक्ष नीति और IN-SPACe मानदंडों के तहत मान्यता प्राप्त निपटान प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, जिसमें कुछ मिशनों के लिए पाँच वर्ष के कक्षीय क्षय का दिशानिर्देश शामिल है। LVM3-M5 का ऊपरी चरण 30 जुलाई 2026 को अटलांटिक महासागर के ऊपर पुनः प्रवेश कर गया।

महत्वपूर्ण दिवस समाचार

- विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को शेरों के संरक्षण और उनके जंगली आवासों के सामने मौजूद खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। शेर शीर्ष शिकारी हैं, जो शिकार की आबादी को नियंत्रित करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रमुख खतरों में आवास का नुकसान, विखंडन, मानव-वन्यजीव संघर्ष, शिकार प्रजातियों में कमी, अवैध शिकार, अवैध वन्यजीव व्यापार, रोग और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। भारत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एशियाई शेरों की जंगली आबादी वाला एकमात्र देश है, जो मुख्यतः गुजरात के गिर परिदृश्य में केंद्रित है। प्रोजेक्ट लायन, जिसे 2020 में शुरू किया गया था, ग्रेटर गिर परिदृश्य में आवास प्रबंधन, आबादी की निगरानी, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने पर केंद्रित है।
- विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को स्वदेशी लोगों के अधिकारों, संस्कृतियों, परंपराओं और योगदानों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में इस दिवस की घोषणा की थी, जिसमें 9 अगस्त 1982 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी आबादी पर कार्य समूह के प्रथम सत्र को स्मरण किया गया। 2026 की थीम, "स्वदेशी दाइयों का सम्मान: जीवन और कल्याण की सुरक्षा", गर्भावस्था, प्रसव, मातृत्व और सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को रेखांकित करती है। यह दिवस आत्मनिर्णय, सांस्कृतिक संरक्षण, भाषा अधिकार, पारंपरिक ज्ञान, भूमि अधिकार, समानता, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देता है तथा विस्थापन, भेदभाव, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुँच जैसे मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करता है।
- अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2026 को "विभिन्न संदर्भ, समान आकांक्षाएँ" विषय के तहत मनाया गया। यह विषय इस बात पर प्रकाश डालता है कि युवा अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक

परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, जबकि उनमें गरिमा, अवसर, शिक्षा, सम्मानजनक रोजगार और बेहतर भविष्य की समान आकांक्षाएँ होती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने महासभा द्वारा 1999 में इस दिवस को घोषित किए जाने के बाद पहली बार इसे 12 अगस्त 2000 को मनाया था। यह दिवस निर्णय लेने में युवाओं की भागीदारी, डिजिटल समावेशन, रोजगार, शिक्षा, कल्याण और जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है। यह युवाओं को विकास, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन में आवश्यक भागीदार के रूप में मान्यता देता है और उनकी विविध चुनौतियों का समाधान करने वाली नीतियों पर जोर देता है।

- विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त 2026 को अफ्रीकी और एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया गया। 2026 का संदेश, "हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करना", सामूहिक संरक्षण पर जोर देता है। प्रमुख खतरों में आवास का नुकसान, खंडित प्रवास गलियारे, अवैध शिकार, अवैध हाथीदाँत व्यापार, मानव-हाथी संघर्ष और बंदी हाथियों के साथ दुर्व्यवहार शामिल हैं। इस दिवस की शुरुआत 2012 में एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन तथा फिल्म निर्माता पेट्रीशिया सिम्स और माइकल क्लार्क की पहल के माध्यम से हुई थी। भारत एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ विश्व की जंगली एशियाई हाथी आबादी का 60% से अधिक हिस्सा पाया जाता है। प्रोजेक्ट एलीफेंट, जिसे 1992 में शुरू किया गया था, आवास संरक्षण और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने में सहायता करता है।
- विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने, भ्रातियों को दूर करने और लोगों को मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रत्यारोपण से अंग विफलता से पीड़ित रोगियों की जान बचाई जा सकती है। गुर्दे, हृदय, यकृत, फेफड़े, अग्न्याशय और आँतें प्रमुख प्रत्यारोपण योग्य अंगों में शामिल हैं। जीवित दाता एक गुर्दा या यकृत के कुछ हिस्से तथा कुछ अन्य अंग दान कर सकते हैं। रॉनल्ड ली हेरिक 1954 में अपने जुड़वाँ भाई को गुर्दा दान करके सफल जीवित गुर्दा दाता बनने वाले पहले व्यक्ति बने, जबकि सर्जन जोसेफ मरे को बाद में प्रत्यारोपण के क्षेत्र में प्रगति के लिए 1990 का नोबेल पुरस्कार मिला। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस की शुरुआत 2010 में हुई और 2023 में इसे 3 अगस्त को मनाया जाने लगा।
- विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिसे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से भी जाना जाता है, 14 अगस्त 2026 को 1947 में भारत के विभाजन के पीड़ितों और जीवित बचे लोगों को याद करने के लिए मनाया गया। भारत सरकार ने 2021 में इस दिवस की घोषणा की थी और उसी वर्ष पहली बार इसे मनाया गया। विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन, सांप्रदायिक हिंसा, जनहानि, संपत्ति और आजीविका का नुकसान तथा परिवारों का बिछड़ना हुआ, विशेष रूप से पंजाब और बंगाल में। यह लॉर्ड माउंटबेटन की 3 जून योजना के बाद हुआ, जबकि सीमाओं का निर्धारण रेडक्लिफ आयोग द्वारा किया गया था। यह दिवस प्रदर्शनियों, तस्वीरों, दस्तावेजों और मौखिक इतिहासों के माध्यम से इन स्मृतियों को संरक्षित करता है तथा सद्भाव, एकता, सहिष्णुता और राष्ट्रीय मेल-मिलाप को बढ़ावा देता है।

निधन संबंधी समाचार

- प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक और मार्क्सवादी सिद्धांतकार एम. पी. परमेश्वरन का 11 अगस्त 2026 को केरल के त्रिशूर स्थित उनके आवास पर 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1935 में जन्मे, उन्होंने तिरुवनंतपुरम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 1965 में मास्को पावर इंस्टीट्यूट से परमाणु इंजीनियरिंग में पीएचडी प्राप्त की। उन्होंने 1957 से 1975 तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में कार्य किया, इसके बाद विज्ञान के लोकप्रियकरण, जमीनी स्तर की शिक्षा और जन सक्रियता पर ध्यान केंद्रित किया। वे केरल शास्त्र साहित्य परिषद से जुड़े रहे और ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क की स्थापना में योगदान दिया। उन्होंने मलयालम भाषा प्रौद्योगिकी में भी योगदान दिया और उन्हें 2022 में केरल श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- प्रमुख आधुनिक भारतीय इतिहासकार सुमित सरकार का 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में उम्र संबंधी लंबे समय से चली आ रही बीमारी के बाद 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 1939 में कलकत्ता में हुआ था। वे इतिहासकार सुभोशन चंद्र सरकार और सांख्यिकीविद् प्रशांत चंद्र महालनोबिस से जुड़े एक विद्वान बंगाली

परिवार से थे। सरकार मार्क्सवादी अध्ययन, राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद और सामाजिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रमुख कृतियों में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन, 1903-1908 और आधुनिक भारत: 1885-1947 शामिल हैं, जिनमें "नीचे से इतिहास" और किसानों, श्रमिकों, आदिवासी समूहों तथा अन्य गैर-अभिजात समुदायों के अनुभवों पर जोर दिया गया। उन्होंने 1974 से 2004 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन किया और 2004 में रवींद्र पुरस्कार प्राप्त किया।

- भारत ने 15 अगस्त 2026 को अपना 80वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया, जो 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्ति के 79 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। यह अवसर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का सम्मान करता है और एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक तथा संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत की यात्रा का उत्सव मनाता है। मुख्य समारोह नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित होता है, जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 2026 की थीम "युवा शक्ति" है, जो नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान, खेल और राष्ट्रीय विकास में युवा भारतीयों की भूमिका को रेखांकित करती है। यह विकसित भारत @2047 के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता की शताब्दी तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है।

स्थिर तथ्य

पहलू	विवरण
उत्तराखंड	मुख्यमंत्री: पुष्कर धामी, राज्यपाल: गुरमीत सिंह, राजधानी: देहरादून (शीतकालीन)
राजस्थान	मुख्यमंत्री: भजनलाल शर्मा, राज्यपाल: हरिभाऊ बागडे, राजधानी: जयपुर
गुजरात	मुख्यमंत्री: भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल: आचार्य देवव्रत, राजधानी: गांधीनगर
आंध्र प्रदेश	मुख्यमंत्री: चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल: अब्दुल नज़ीर, राजधानी: अमरावती
असम	मुख्यमंत्री: हिमंत सरमा, राज्यपाल: लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राजधानी: ईटानगर
महाराष्ट्र	मुख्यमंत्री: देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल: जिष्णु देव वर्मा, राजधानी: मुंबई
छत्तीसगढ़	मुख्यमंत्री: मोहन माझी, राज्यपाल: रमेश डेका, राजधानी: रायपुर
तमिलनाडु	मुख्यमंत्री: जोसेफ विजय, राज्यपाल: आर. अलेकर, राजधानी: चेन्नई
अमेरिका	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रंप
वेनेजुएला	राष्ट्रपति: डेल्सी रोड्रिगेज़
नेपाल	प्रधानमंत्री: बालेन शाह
भारतीय रिज़र्व बैंक	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा
डीबीएस बैंक	सीएमडी एवं एमडी: रजत वर्मा



ALL EXAMS, **ONE** SUBSCRIPTION

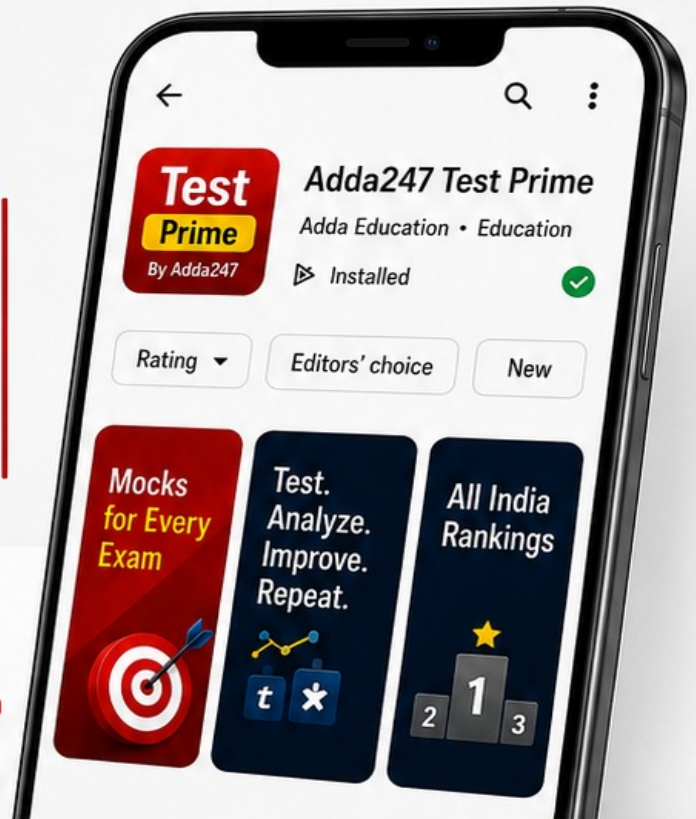


Test. Analyze. Improve. Repeat.



*Don't just
prepare.
Perform.*

Test Prime – built only
for mock tests.



1,50,000+
Mock Tests



25,000+
Previous Year
Papers



800+
Exam
Covered



500%
Refund on
Selection



5 lakh+
Free Quizzes



Daily
Free PDFs



Top Alerts
Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- ✓ Multilingual
- ✓ Detailed Solution
- ✓ Strong and Weak Areas
- ✓ All India Rankings



Safe & Reliable



Trusted by
Lakhs of Aspirants



Your Success,
Our Mission



**DOWNLOAD
TEST PRIME**

Your Success Partner!

